www.railsamacharbureau.com

सम्पूर्ण भारतीय रेल जगत का प्रथम पाक्षिक, प्रयागराज से प्रकाशित

रेल समाचार ब्यूरो

सन् 1990 से रेल सेवा में समर्पित

"भारत की विकास यात्रा में रेलवे केवल परिवहन का माध्यम नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की आधारशिला रहा है।"

"भारतीय रेल ने समय के साथ स्वयं को बदला है, ताकि बदलते भारत की जरूरतों के साथ कदम मिलाया जा सके।"

वर्ष-36 अंक:15-16 रेल समाचार ब्यूरो प्रयागराज 01 अगस्त - 31 अगस्त 2026 पृष्ठ 12, (सयुक्तांक) मूल्य:20 रु. मात्र. डाक खर्च (रंगीन सहित)

21 गुना बढ़ा आधुनिक रेल कोच उत्पादन, हाइड्रोजन ट्रेन से हाई-स्पीड रेल तक पीएम मोदी ने दिखाया रेलवे का नया विजन

सूत्र/रे.स.ब्यू - प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को लाल किले से दिए 80वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में भारतीय रेल के बदलते स्वरूप और भविष्य की दिशा को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में आधुनिक रेलवे कोचों का उत्पादन 21 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री ने इसे देश में तेजी से हो रहे आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में पेश किया।

रेलवे के विद्युतीकरण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 1925 में शुरू हुआ विद्युतीकरण कार्य 90 वर्षों में करीब 30 प्रतिशत नेटवर्क तक पहुंचा था, जबकि पिछले एक दशक में शेष 70 प्रतिशत का काम पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि इससे डीजल आयात पर निर्भरता कम हुई और पर्यावरण को भी लाभ मिला।

प्रधानमंत्री ने भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का भी उल्लेख किया और इसे अपनी श्रेणी की सबसे लंबी और शक्तिशाली ट्रेनों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने हाइड्रोजन आधारित रेल परिवहन के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई है।

भविष्य की कनेक्टिविटी को लेकर प्रधानमंत्री ने गति शक्ति को विकास की सात प्रमुख धाराओं में शामिल करते हुए शहरों को हाई-स्पीड रेल से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने आधुनिक हाईवे, अंतर्देशीय जलमार्ग, एयरपोर्ट और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स के साथ तेज और निर्बाध कनेक्टिविटी विकसित करने की आवश्यकता बताई।

प्रधानमंत्री के संबोधन में रेलवे की तस्वीर केवल तेज रफ्तार ट्रेनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आधुनिक कोच निर्माण, विद्युतीकरण, हाइड्रोजन तकनीक और हाई-स्पीड रेल के जरिए 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य से जुड़ी व्यापक परिवहन व्यवस्था का विज़न सामने आया।

1853 से 2026 तक: रफ्तार, तकनीक और बदलाव की भारतीय रेल यात्रा

सूत्र/रे.स.ब्यू - 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे से ठाणे के बीच चली भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी ने करीब 35 किलोमीटर की दूरी तय की थी। 14 डिब्बों और लगभग 400 यात्रियों से शुरू हुई यह यात्रा आज एक ऐसे विशाल रेल नेटवर्क में बदल चुकी है, जो प्रतिदिन हजारों ट्रेनों के जरिए देश के करोड़ों लोगों को जोड़ता है। स्वतंत्रता के बाद अलग-अलग रेलवे व्यवस्थाओं को एकीकृत कर भारतीय रेल को राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया और समय के साथ इसका विस्तार देश के कोने-कोने तक हुआ।

भाप इंजनों के दौर से शुरू हुई भारतीय रेल की यात्रा अब विद्युतीकरण, आधुनिक ट्रेनों, डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक पहुंच चुकी है। मार्च 2026 तक ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका था। इसके साथ ट्रैक नवीनीकरण, गति बढ़ाने और आधुनिक संचार प्रणालियों पर भी लगातार काम हुआ है। वंदे भारत एक्सप्रेस इस बदलाव की प्रमुख पहचान बनी है, वहीं जनवरी 2026 में शुरू हुई वंदे भारत शयनयान सेवा ने आधुनिक रेल यात्रा को लंबी दूरी तक विस्तार दिया। अमृत भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत स्टेशन योजना के जरिए बेहतर सुविधाएं आम यात्रियों तक पहुंचाई जा रही हैं।

सुरक्षा के क्षेत्र में स्वदेशी कवच प्रणाली, एआई आधारित वीडियो निगरानी और आधुनिक यात्री सूचना प्रणालियां रेलवे को अधिक सुरक्षित और स्मार्ट बना रही हैं। माल परिवहन में भी रेलवे ने रिकॉर्ड लदान दर्ज कर अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत की है।

अब भारतीय रेल हाई-स्पीड रेल के नए दौर में प्रवेश कर रही है। मुंबई अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना और प्रस्तावित नए गलियारे भविष्य की तेज रफ्तार कनेक्टिविटी की तस्वीर पेश करते हैं। वहीं 17 जुलाई 2026 को जींद सोनीपत रेलखंड पर शुरू हुई स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन हरित परिवहन की दिशा में नई पहल है।

1853 की 35 किलोमीटर की यात्रा से 2026 की हाई-स्पीड, इलेक्ट्रिक और डिजिटल रेल तक का सफर केवल तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि बदलते भारत की कहानी है। भारतीय रेल अब सिर्फ यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने का माध्यम नहीं, बल्कि विकास, आत्मनिर्भरता और भारत की बढ़ती गति की मजबूत आधारशिला बन चुकी है।

रेल भवन में गूंजा देशभक्ति का जोश, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निकाली तिरंगा रैली

सूत्र/रे.स.ब्यू - स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रेल भवन देशभक्ति के रंग में रंग गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 अगस्त को रेल भवन परिसर में तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ सतीश कुमार समेत बोर्ड के सदस्यों, महानिदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों ने रैली में भाग लेकर राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का संदेश दिया।

भारतीय रेलवे 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत कई विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 10 अगस्त को क्विज प्रतियोगिता, 11 अगस्त को देशभक्ति गीतों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और 14 अगस्त को 'वंदे मातरम्' का सामूहिक गायन आयोजित किया गया। इन आयोजनों के जरिए भारतीय रेलवे ने देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को और मजबूत करने का संदेश दिया।

भारतीय रेलवे का बड़ा सुरक्षा नेटवर्क: 3,215 स्टेशन और 13,409 यात्री डिब्बे CCTV की निगरानी में

सूत्र/रे.स.ब्यू - भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से देशभर में रेलवे स्टेशनों और यात्री डिब्बों में चरणबद्ध तरीके से सीसीटीवी निगरानी प्रणाली का विस्तार किया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में जानकारी दी कि अब तक 3,215 रेलवे स्टेशनों और 13,409 यात्री डिब्बों में सीसीटीवी प्रणाली स्थापित की जा चुकी है। इसके अलावा, वर्तमान में परिचालनरत सभी वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन रेक पहले ही सीसीटीवी कैमरों से लैस किए जा चुके हैं।

रेल मंत्री के अनुसार, रेलवे स्टेशनों, यात्री डिब्बों और अन्य रेलवे परिसरों में निगरानी व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए सीसीटीवी प्रणाली का विस्तार लगातार जारी है। स्टेशन परिसरों में लगाए गए कैमरों को एआई-आधारित वीडियो विश्लेषण सुविधाओं से जोड़ा गया है। इन प्रणालियों के माध्यम से अनधिकृत प्रवेश, किसी व्यक्ति के लंबे समय तक संदिग्ध रूप से एक स्थान पर ठहरने और प्लेटफार्म या परिसर में किसी व्यक्ति के गिरने जैसी घटनाओं का स्वतः पता लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 तथा जून 2026 तक इन एआई-सक्षम सीसीटीवी प्रणालियों की मदद से 9,840 सुरक्षा संबंधी घटनाओं का पता लगाया गया।

जोनवार आंकड़ों के अनुसार, उत्तरी रेलवे में सबसे अधिक 425 रेलवे स्टेशन सीसीटीवी निगरानी प्रणाली से जुड़े हैं। इसके बाद पश्चिमी रेलवे में 391 स्टेशन और पूर्वी रेलवे में 271 स्टेशन सीसीटीवी कवरेज के दायरे में हैं। वहीं, यात्री डिब्बों में सीसीटीवी स्थापना के मामले में पश्चिमी रेलवे 1,735 कोचों के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद उत्तरी रेलवे में 1,483 कोच और दक्षिणी रेलवे में 1,481 कोच सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित हैं।

रेल मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, मध्य रेलवे में 240 स्टेशन और 1,384 कोच, पूर्व मध्य रेलवे में 237 स्टेशन और 617 कोच, पूर्व तटीय रेलवे में 80 स्टेशन और 601 कोच, उत्तर मध्य रेलवे में 141 स्टेशन और 339 कोच, उत्तर पूर्वी रेलवे में 93 स्टेशन और 758 कोच, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में 94 स्टेशन और 410 कोच, उत्तर पश्चिमी रेलवे में 35 स्टेशन और 261 कोच, दक्षिण मध्य रेलवे में 30 स्टेशन और 947 कोच, दक्षिण तटीय रेलवे में 202 स्टेशन और 415 कोच, दक्षिण पूर्वी रेलवे में 197 स्टेशन और 665 कोच, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में 145 स्टेशन और 303 कोच, दक्षिण पश्चिमी रेलवे में 195 स्टेशन और 452 कोच, पश्चिम मध्य रेलवे में 170 स्टेशन और 270 कोच सीसीटीवी प्रणाली से लैस किए जा चुके हैं। इसके अलावा, मेट्रो रेलवे, कोलकाता के 57 स्टेशन तथा कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 72 स्टेशन भी सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के दायरे में हैं।

रेल मंत्री ने कहा कि सीसीटीवी प्रणाली की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है और यात्रियों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए भारतीय रेलवे पूरे नेटवर्क में निगरानी व्यवस्था का विस्तार जारी रखे हुए है। यह जानकारी केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 24 जुलाई को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

यात्री सुरक्षा एवं पारदर्शिता की दिशा में प्रयागराज मंडल की अभिनव पहल, अब बॉडी वॉर्न कैमरा पहनकर ड्यूटी करेंगे टिकट चेकिंग कर्मचारी

सूत्र/रे.स.ब्यू - मंडल रेल प्रबंधक, प्रयागराज मंडल श्री रजनीश अग्रवाल के नेतृत्व में एवं वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कोचिंग श्री हरिमोहन के मार्गानिर्देशन में उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल द्वारा यात्रियों की सुरक्षा, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं अभिनव पहल करते हुए दिनांक 24 जुलाई, 2026 से बॉडी वॉर्न कैमरा (Body Worn Camera&BWC) पायलट परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत टिकट चेकिंग कर्मचारी ड्यूटी के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरा पहनकर टिकट जांच करेंगे, जिससे टिकट जांच के दौरान होने वाली प्रत्येक गतिविधि वीडियो एवं ऑडियो सहित रिकॉर्ड होगी।

यह पायलट परियोजना महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे श्री नरेश पाल सिंह के विशेष निर्देशों के अनुपालन में प्रारंभ की गई है। प्रथम चरण में प्रयागराज मंडल की दो प्रमुख प्रीमियम ट्रेनों 12417/12418 प्रयागराज एक्सप्रेस (प्रयागराज नई दिल्ली प्रयागराज) तथा 12451/12452 श्रमशक्ति एक्सप्रेस (कानपुर नई दिल्ली कानपुर) में कार्यरत टिकट चेकिंग कर्मचारियों को बॉडी वॉर्न कैमरे उपलब्ध कराए गए हैं। पायलट परियोजना के सफल क्रियान्वयन एवं प्राप्त अनुभवों के आधार पर इस व्यवस्था का विस्तार चरणबद्ध रूप से प्रयागराज मंडल से प्रारंभ होने वाली अन्य ट्रेनों में भी किया जाएगा।

रेलवे द्वारा उपलब्ध कराए गए बॉडी वॉर्न कैमरे अत्याधुनिक तकनीक से युक्त हैं, जिनमें एचडी (HD) वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, नाइट विजन, लंबी अवधि का बैटरी बैकअप तथा टैंपर-प्रूफ रिकॉर्डिंग प्रणाली जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इन विशेषताओं के कारण लंबी दूरी की यात्रा के दौरान भी निर्बाध रिकॉर्डिंग सुनिश्चित होगी तथा रिकॉर्ड किए गए डेटा के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना नहीं रहेगी।

टिकट जांच के दौरान कई बार यात्रियों एवं टिकट चेकिंग कर्मचारियों के मध्य विवाद अथवा शिकायतें उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में कैमरे में उपलब्ध रिकॉर्डिंग निष्पक्ष एवं विश्वसनीय साक्ष्य के रूप में कार्य करेगी, जिससे वास्तविक तथ्यों के आधार पर शिकायतों का त्वरित एवं निष्पक्ष निस्तारण संभव होगा। इससे निराधार अथवा फर्जी शिकायतों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। साथ ही यदि किसी यात्री के साथ अनुचित व्यवहार अथवा किसी कर्मचारी के साथ अभद्रता, दुर्व्यवहार या मारपीट जैसी घटना होती है, तो उसकी सत्यता का भी निष्पक्ष परीक्षण किया जा सकेगा।

यह व्यवस्था टिकट चेकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं व्यावसायिक आचरण को और अधिक सुदृढ़ बनाएगी। साथ ही यात्रियों एवं टिकट चेकिंग कर्मचारियों दोनों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा मिलेगा तथा टिकट जांच के दौरान अनुशासन एवं शालीन व्यवहार को प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

इस प्रणाली से प्राप्त होने वाले प्रमुख लाभ

- टिकट चेकिंग प्रक्रिया का निष्पक्ष एवं डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा।
- यात्रियों एवं टिकट चेकिंग कर्मचारियों दोनों के हितों का समान रूप से संरक्षण होगा।
- फर्जी शिकायतों एवं अनावश्यक विवादों में उल्लेखनीय कमी आएगी।
- शिकायतों एवं अपीलों के निस्तारण में साक्ष्य आधारित एवं त्वरित निर्णय लिए जा सकेंगे।
- कर्मचारियों के कार्य निष्पादन, व्यवहार एवं सेवा गुणवत्ता का अधिक प्रभावी मूल्यांकन संभव होगा।
- सुरक्षा संबंधी घटनाओं, संदिग्ध गतिविधियों अथवा कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में उपलब्ध वीडियो फुटेज रेलवे सुरक्षा बल (RPF) एवं अन्य जांच एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण साक्ष्य सिद्ध होगी।
- यात्रियों का रेलवे के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होगा तथा रेलवे की सकारात्मक छवि को बढ़ावा मिलेगा।
- डिजिटल तकनीक के प्रभावी उपयोग से रेलवे प्रशासन में सुशासन (Good Governance), पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को और अधिक मजबूती मिलेगी।

अब AI करेगा फैसला, AC कोच में यात्रियों तक पहुंचेगा सिर्फ साफ और हाइजीनिक बेडरोल

सूत्र/रे.स.ब्यू - एसी कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को मिलने वाले बेड लिनन की गुणवत्ता सुधारने के लिए भारतीय रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित नई तकनीक का परीक्षण शुरू किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट को फिलहाल सेंट्रल रेलवे के पुणे डिवीजन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के जयपुर व जोधपुर डिवीजन की मशीनीकृत रेलवे लॉन्ड्री में लागू किया गया है। जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

इस व्यवस्था में AI से लैस कैमरा सिस्टम धुलाई के बाद चादर, तकिए के कवर और अन्य बेड लिनन की जांच करता है। यदि किसी लिनन पर दाग रह जाते हैं या उसकी सफाई संतोषजनक नहीं होती, तो सिस्टम उसे स्वतः चिन्हित कर देता है। इसके बाद ही साफ और उपयुक्त बेडरोल को पैक कर यात्रियों के उपयोग के लिए भेजा जाता है।

रेलवे का मानना है कि इस तकनीक के इस्तेमाल से बेड लिनन की गुणवत्ता जांच अधिक सटीक और एक समान होगी। साथ ही, निरीक्षण के लिए मानवीय हस्तक्षेप पर निर्भरता भी कम होगी, जिससे यात्रियों को अधिक स्वच्छ और हाइजीनिक बेडरोल उपलब्ध कराए जा सकेंगे और उनका यात्रा अनुभव बेहतर होगा

इस पहल के साथ ही भारतीय रेलवे ने नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की सेवाओं तथा कामाख्या-हावड़ा के बीच हाल ही में शुरू हुई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में एसी यात्रियों के लिए कंबल कवर के उपयोग का दायरा भी बढ़ाया है।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में मध्य रेल ने स्क्रैप बिक्री से अर्जित किए ₹136.10 करोड़ - पिछले पाँच वर्षों की पहली तिमाही का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन

सूत्र/रे.स.ब्यू - मध्य रेल ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अपने सभी पाँच मंडलों एवं कारखानों में ''मिशन जीरो स्क्रैप स्टेटस'' को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। इस अभियान का उद्देश्य रेलवे के कबाड़ (स्क्रैप) को मूल्यवान राजस्व-सृजनकारी परिसंपत्ति में परिवर्तित करना तथा संसाधनों का प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है।

मध्य रेल के स्टोर्स विभाग द्वारा दूर-दराज एवं बिखरे हुए स्थानों सहित सभी पाँचों मंडलों में पड़े स्क्रैप की पहचान कर उसके व्यवस्थित निस्तारण के लिए व्यापक एवं समन्वित अभियान चलाए गए। इन विशेष प्रयासों के परिणामस्वरूप स्क्रैप बिक्री से होने वाली आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

पहली तिमाही (अप्रैल जून 2026) में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन । वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून 2026) के दौरान मध्य रेल ने स्क्रैप बिक्री से 136.10 करोड़ का राजस्व अर्जित किया।

यह पिछले पाँच वर्षों की पहली तिमाही का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है इससे पूर्व पहली तिमाही में स्क्रैप बिक्री से प्राप्त राजस्व वित्त वर्ष 2025-26 में 71.94 करोड़, 2024-25 में 81.09 करोड़, 2023-24 में 81.64 करोड़ तथा 2022-23 में 101.40 करोड़ रहा था।

यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही की तुलना में स्क्रैप बिक्री से प्राप्त राजस्व में 89 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि को भी दर्शाती है। स्क्रैप बिक्री में मुंबई मंडल ने 22.43 करोड़ की सर्वाधिक आय अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके बाद भुसावल मंडल ने 20.44 करोड़, नागपुर मंडल ने 19.98 करोड़, पुणे मंडल ने 18.19 करोड़ तथा सोलापुर मंडल ने 6.44 करोड़ की स्क्रैप बिक्री दर्ज की। इसके अतिरिक्त परेल एवं माटुंगा कारखानों तथा मध्य रेल के अन्य स्थानों पर स्थित शेडों एवं इकाइयों ने सामूहिक रूप से 48.62 करोड़ की स्क्रैप बिक्री कर महत्वपूर्ण योगदान दिया।

यह उपलब्धि विभिन्न प्रकार के स्क्रैप एवं अनुपयोगी सामग्रियों के व्यवस्थित निस्तारण के माध्यम से प्राप्त की गई है। इनमें मुख्य रूप से रेल परमानेंट-वे (Permanent Way) के स्लीपर, लौह एवं अलौह धातु (फेरस एवं नॉन-फेरस) स्क्रैप, अनुपयोगी (कंडेम्ड) कोच एवं वैगन तथा अन्य कबाड़ सामग्री शामिल हैं।

यह उल्लेखनीय उपलब्धि ''मिशन जीरो स्क्रैप स्टेटस'' के प्रति मध्य रेल की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ ही यह वित्तीय अनुशासन, परिचालन दक्षता, संसाधनों के प्रभावी उपयोग तथा पर्यावरणीय सततता को बढ़ावा देने की दिशा में मध्य रेल के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है।

रेल सुरक्षा में बड़ा सुधार, गंभीर हादसे घटकर दो: सुरक्षा पर खर्च ₹1.20 लाख करोड़ के पार

सूत्र/रे.स.ब्यू - भारतीय रेलवे ने आधुनिक तकनीक, बेहतर रखरखाव और सुरक्षा संबंधी उपायों के जरिए रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि वर्ष 2014-15 में जहां गंभीर रेल दुर्घटनाओं की संख्या 135 थी, वहीं अब यह आंकड़ा घटकर केवल दो रह गया है।

रेल मंत्री ने कहा कि सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में निवेश में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। उनके अनुसार, वर्ष 2013-14 में सुरक्षा संबंधी कार्यों पर लगभग 39 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जबकि वर्ष 2026-27 में यह राशि बढ़कर 1.20 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। लोको पायलटों की सतर्कता बढ़ाने के उद्देश्य से रेलवे ने सभी लोकोमोटिव में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस (Vigilance Control Device) स्थापित किए हैं। यह प्रणाली संचालन के दौरान लोको पायलट की सक्रियता पर नजर रखने में मदद करती है।

रेल मंत्री ने बताया कि स्वदेशी तकनीक पर आधारित 'कवच 4.0' प्रणाली का विस्तार भी तेजी से किया जा रहा है। अब तक इसे लगभग 2,500 किलोमीटर रेल मार्ग पर सफलतापूर्वक चालू किया जा चुका है। इसमें देश के सबसे व्यस्त रेल कॉरिडोर माने जाने वाले दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा मार्ग भी शामिल हैं। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग, बुनियादी ढांचे के बेहतर रखरखाव और सुरक्षा उपायों के लगातार विस्तार के कारण भारतीय रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुई है।

पाठकों से अनुरोध

विगत वर्षों की भाँति आगामी वर्ष के लिए अपनी रेल समाचार ब्यूरो पत्रिका को सुरक्षित करने के लिए वार्षिक सद्स्यता शुल्क शीघ्र भेजने की कृपा करें, जिससे उक्त पत्रिका आपको नियमित भेजी जा सके।

सहयोग राशि:

१. उच्चतम अधिकारी-5000 रु. मात्र
२. उच्च अधिकारी- 3500 रु. मात्र
३. अधीनस्थ अधिकारी-2500 रु. मात्र
४. रेलकर्मी/अन्य सदस्य-1000 रु. मात्र

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव

पंजिकृत कार्यालाय

502 पंचशीला भवन त्रिवेनी रोड, नेतानगर, कीडगंज प्रयागराज-211003 से प्रकाशित।

कैंप कार्यालय- अनिल केन (रिर्पोटर) कार्यालय 8439 आर्य नगर पहाड़गंज दिल्ली-55

समस्त प्रकार के कानूनी मामलों का न्यायिक क्षेत्र प्रयागराज होगा

सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
दि. इलाहाबाद ब्लॉक वर्क्स प्रा. लि.
329/255 चक. जीरो रोड इलाहाबाद से मुद्रित एवं 502 पंचशीला भवन त्रिवेनी रोड, नेतानगर, कीडगंज प्रयागराज-211003 से प्रकाशित।
आर.एन. आई नं. 51097-90 पोस्ट ए.डी.-8
मो. 9773946044 / 9793956044
फोन नं. 0532-2418040

75 नए अमृत भारत स्टेशन राष्ट्र को समर्पित, पीएम मोदी ने दी विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की हाइड्रोजन ट्रेन पूर्णतया प्रदूषण मुक्त होने के साथ ही, 'मेक इन इंडिया' की एक उल्लेखनीय सफलता का प्रमाण है

सूत्र/रे.स.ब्यू - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर से वर्चुअल माध्यम से 20 राज्यों में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। लगभग 1,570 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक बनाए गए इन स्टेशनों को यात्री-अनुकूल सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है और इनके डिजाइन में स्थानीय संस्कृति, विरासत तथा वास्तुकला को स्थान दिया गया है। पुनर्विकसित स्टेशनों में पंजाब, गुजरात, ओडिशा और दक्षिणी रेलवे के कई प्रमुख स्टेशन शामिल हैं।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने करतोली अंबाला रेल सेवा तथा अमृतसर (छेहर्टा) वाराणसी संत रविदास एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भारतीय रेलवे में हुए तेज बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और नए अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा सरकार 'नागरिक देवो भव' के मंत्र से प्रेरित होकर कार्य कर रही है।

रेलवन ऐप ने बदली रेलवे टिकटिंग की तस्वीर, 4.55 करोड़ डाउनलोड के साथ रोजाना 9.65 लाख टिकट बुक

सूत्र/रे.स.ब्यू - भारतीय रेलवे की डिजिटल सेवाओं को यात्रियों से लगातार बेहतर प्रतिक्रिया मिल रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण RailOne (रेलवन) ऐप है, जिसे अब तक 4.55 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रतिदिन औसतन 9.65 लाख टिकट बुक हो रहे हैं। वहीं, ऑनलाइन टिकटिंग को सुरक्षित बनाने के लिए रेलवे ने जनवरी 2024 से 30 जून 2026 तक 6.68 करोड़ से ज्यादा संदिग्ध यूजर अकाउंट स्थायी रूप से निष्क्रिय किए हैं।

1 जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए RailOne ऐप को यात्रियों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। इसके माध्यम से आरक्षित और अनारक्षित टिकट बुकिंग के अलावा प्लेटफॉर्म टिकट, पीएनआर स्टेटस, ट्रेन की लाइव जानकारी और रेलमदद जैसी सुविधाएं एक ही ऐप पर उपलब्ध हैं। रेलवे के अनुसार, वर्तमान में रोजाना करीब 2.75 लाख आरक्षित और 6.89 लाख अनारक्षित टिकट इसी ऐप के जरिए जारी किए जा रहे हैं।

रेल मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, जून 2025 से जून 2026 के बीच 65.08 करोड़ आरक्षित टिकट बुक हुए। इनमें 57.90 करोड़ टिकट ऑनलाइन माध्यम से खरीदे गए, जो कुल बुकिंग का 89 प्रतिशत है। वही, 7.18 करोड़ टिकट रेलवे आरक्षण काउंटरों से जारी किए गए। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि यात्रियों का भरोसा तेजी से डिजिटल टिकटिंग व्यवस्था की ओर बढ़ा है।

ऑनलाइन टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए रेलवे ने कई स्तरों पर निगरानी व्यवस्था मजबूत की है। संदिग्ध मोबाइल नंबर, ईमेल डोमेन और आईपी एड्रेस की पहचान के आधार पर 6.68 करोड़ से अधिक खातों को निष्क्रिय किया गया, जबकि 6.22 करोड़ से ज्यादा अकाउंट दोबारा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक अस्थायी रूप से निलंबित रखे गए। तत्काल टिकट और अग्रिम आरक्षण अवधि (ARP) के तहत टिकट बुकिंग के लिए आधार सत्यापन को अनिवार्य बनाया गया है। कुछ ट्रेनों में आधार आधारित ओटीपी सत्यापन भी लागू किया गया है, जिससे फर्जी पहचान के जरिए टिकट बुकिंग और ऑटोमेटेड बॉट्स के इस्तेमाल पर प्रभावी नियंत्रण मिला है।

रेलवे ने अपनी डिजिटल टिकटिंग प्रणाली की सुरक्षा के लिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (CDN), वेब एप्लिकेशन फायरवॉल, एंटी-बॉट सिस्टम, डीडीओएस सुरक्षा और सुरक्षित डीएनएस जैसी आधुनिक साइबर सुरक्षा तकनीकों को अपनाया है। पिछले छह महीनों के दौरान औसतन 57.74 प्रतिशत फर्जी बॉट ट्रैफिक को सफलतापूर्वक रोका गया, जिससे वास्तविक यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग प्रक्रिया अधिक सुगम बनी। यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए संचालित 'रेलमदद' प्लेटफॉर्म ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2025-26 में इस पोर्टल पर 6,94,368 मामलों का समाधान किया गया, जिनमें 89.49 प्रतिशत यात्रियों ने सेवा को उत्कृष्ट या संतोषजनक बताया। वहीं, पिछले तीन वर्षों में शिकायतों के निस्तारण की सफलता दर लगभग 99.98 प्रतिशत रही।

टिकटों की अवैध खरीद-फरोख्त और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ भी रेलवे की कार्रवाई लगातार जारी है। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने वर्ष 2021 से जून 2026 तक 22,676 कथित दलालों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा वर्ष 2025-26 और 2026-27 (30 जून 2026 तक) के दौरान राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर संदिग्ध टिकट बुकिंग से जुड़ी 530 शिकायतें दर्ज हुई, जबकि 13,343 संदिग्ध ईमेल डोमेन ब्लॉक किए गए।

आरेडिका में 'वित्त प्रबंधन' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन

सूत्र/रे.स.ब्यू - आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली के राजभाषा विभाग द्वारा 'वित्त प्रबंधन' विषय पर एक तकनीकी कार्यशाला/संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। यह संगोष्ठी आरेडिका एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायबरेली के सदस्य कार्यालयों के लिए आयोजित की गयी।

मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित अभिनव यादव, उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर एवं उप मुख्य राजभाषा अधिकारी, आरेडिका नें कार्यशाला में प्रतिभागियों को व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की । वक्ता द्वारा निवेश के विविध विकल्पों, उनसे जुड़े जोखिमों तथा संभावित लाभ-हानि का व्यावहारिक एवं सरल भाषा में विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। साथ ही वर्तमान समय में बढ़ रहे ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विभिन्न तरीकों जैसे फर्जी निवेश योजनाओं, साइबर ठगी, फिशिंग लिंक, ओटीपी एवं बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करने तथा केवल विश्वसनीय एवं अधिकृत माध्यमों से ही निवेश करने की सलाह दी।

कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को वित्तीय सुरक्षा एवं आर्थिक स्थिरता के लिए आय के स्रोतों में विविधता लाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया तथा विभिन्न वैध एवं व्यवहारिक विकल्पों की जानकारी दी गई।

कार्यशाला के अंत में आयोजित संवादात्मक सत्र में प्रतिभागियों ने निवेश, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, कर नियोजन, सेवानिवृत्ति योजना तथा अन्य वित्तीय विषयों से संबंधित अनेक जिज्ञासाएँ व्यक्त की। मुख्य वक्ता अभिनव यादव ने सभी प्रश्नों एवं शंकाओं का सरल, व्यावहारिक एवं उदाहरणों सहित समाधान किया।

उत्तर मध्य रेलवे ने तैयार किया सोलर-असिस्टेड पैसेंजर कोच: यात्री परिवहन में हरित ऊर्जा की ओर एक नया प्रयास

सूत्र/रे.स.ब्यू -उत्तर मध्य रेलवे ने टिकाऊ और ऊर्जा-कुशल रेल अभियानों की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए पायलट तौर पर सोलर-असिस्टेड (सौर ऊर्जा संचालित) पैसेंजर कोच का निर्माण और कमीशनिंग की है। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्री नरेश पाल सिंह की दूरदर्शी परिकल्पना और प्रयागराज मंडल द्वारा किए गए सफल क्रियान्वयन के तहत इस प्रणाली को 14 जुलाई 2026 को आधिकारिक रूप से कमीशन किया गया। यह अभिनव पहल पारंपरिक रेलवे रोलिंग स्टॉक के साथ आधुनिक नवीकरणीय ऊर्जा तकनीक के एकीकरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है।

पारंपरिक रूप से भारतीय रेल के आईसीएफ (ICF) पैसेंजर कोचों में बिजली का उत्पादन कोच के नीचे लगे 'एक्सल-ड्रिवन अल्टरनेटर' के माध्यम से किया जाता है। यह अल्टरनेटर, जो कोच के पहियों के एक्सल से बेल्ट व्यवस्था द्वारा यांत्रिक रूप से चलता है, कोच के बैटरी बैंक को चार्ज करता है और यात्रियों की सुविधाओं जैसे पंखे, लाइट और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट के लिए बिजली की आपूर्ति करता है। हालांकि इस प्रणाली ने दशकों तक भारतीय रेल की कुशलतापूर्वक सेवा की है, लेकिन यह पूरी तरह से ट्रेन की गति पर निर्भर रहती है और यांत्रिक तथा विद्युत ऊर्जा रूपांतरण के दौरान इसमें ऊर्जा का नुकसान होता है।

सोलर-असिस्टेड कोच इस पारंपरिक व्यवस्था में एक प्रगतिशील और पर्यावरण के अनुकूल सुधार प्रस्तुत करता है। प्रयागराज मंडल द्वारा तैयार किए गए इस पायलट कोच की छत पर लगभग 6.93 किलोवाट पीक क्षमता का उच्च दक्षता वाला सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम लगाया गया है। यह प्रणाली सीधे सूर्य की रोशनी से ऑनबोर्ड स्वच्छ बिजली उत्पन्न करती है और कोच के बैटरी बैंक को चार्ज करने में मदद करती है। दिन भर मिलने वाली सौर ऊर्जा का उपयोग करके यह प्रणाली पारंपरिक एक्सल-ड्रिवन पावर जनरेशन पर निर्भरता को कम करती है, जिससे यांत्रिक घर्षण घटता है और समग्र ऊर्जा उपयोग में सुधार आता है। इसके साथ ही, यह व्यवस्था पारंपरिक चार्जिंग प्रणाली पर भार कम करके ऑनबोर्ड बिजली सेवाओं की विश्वसनीयता बढ़ाती है, बैटरी का जीवनकाल बढ़ाती है और रखरखाव की लागत में कमी लाती है।

आंकड़ों के अनुसार, 6.93 किलोवाट पीक क्षमता का यह सोलर संयंत्र प्रति कोच लगभग 13,400 यूनिट (kWh) स्वच्छ बिजली प्रति वर्ष उत्पन्न करेगा, जिससे रेलवे को प्रति कोच लगभग 2.80 लाख प्रति वर्ष की राजस्व बचत अनुमानित है। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी यह पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रति कोच प्रति वर्ष लगभग 11 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी।

वर्तमान में एक आईसीएफ नॉन-एसी पैसेंजर कोच पर लगाए गए इस पायलट सोलर सिस्टम का संचालन शुरू हो चुका है और इससे निर्बाध विद्युत उत्पादन हो रहा है, जिसकी तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा सतत निगरानी की जा रही है। कार्ययोजना के तहत इस पायलट कोच को एक माह तक गहन निरीक्षण में रखा जाएगा। इसके साथ ही रेलवे कारखाने में प्रति माह 2 कोच की दर से कैंपिंग कोचों में यह सौर प्रणाली स्थापित की जाएगी। इस पायलट प्रोजेक्ट से प्राप्त अनुभवों और प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर इस तकनीक को भविष्य में अन्य पैसेंजर कोचिंग स्टॉक में भी आगे विस्तारित किया जाएगा। यह परियोजना उत्तर मध्य रेलवे की हरित पहलों, तकनीकी नवाचार और ऊर्जा संसाधनों के कुशल उपयोग के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो स्वच्छ और अधिक टिकाऊ परिवहन की दिशा में भारतीय रेल की यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर के. कृष्ण कुमार बने रेलवे बोर्ड में महानिदेशक, रेलवे स्वास्थ्य सेवा

सूत्र/रे.स.ब्यू -उत्तर पश्चिम रेलवे के प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर के. कृष्ण कुमार भारतीय रेल के सर्वोच्च प्रशासनिक स्तर पर रेलवे बोर्ड में महानिदेशक, रेलवे स्वास्थ्य सेवा (डीजी- रेलवे हेल्थ सर्विसेज) का प्रतिष्ठित पद का पदभार संभालेंगे। यह उपलब्धि न केवल उनके उत्कृष्ट कार्य शैली, दूरदर्शी नेतृत्व एवं समर्पित सेवाओं का सम्मान बल्कि उत्तर पश्चिम रेलवे परिवार के लिए भी गर्व का विषय है।

इस अवसर पर उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री पंकज शर्मा ने डॉक्टर के कृष्ण कुमार को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मूल रूप से केरल के पालघाट जिले के, भारतीय रेलवे स्वास्थ्य सेवा 1990 बैच के अधिकारी डॉ के. कृष्ण कुमार ने 26 अगस्त 1991 को रेल सेवा ज्वाइन की। इन्होंने सहायक चिकित्सा मंडल अधिकारी/ भावनगर, मंडल चिकित्सा अधिकारी/ भावनगर, वरिष्ठ मंडल चिकित्सा अधिकारी/भावनगर, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा निदेशक/ वडोदरा, मुख्य चिकित्सा निदेशक/ वडोदरा, मुख्य स्वास्थ्य निदेशक/ पश्चिम रेलवे जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ वडोदरा के पद पर रहते हुए उन्हें पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा स्वास्थ सेवाओं की कुशलता शील्ड तीन बार प्रदान की गई। कोविड-19 के समय भी उन्हें उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया।

डॉक्टर के कृष्ण कुमार ने उत्तर पश्चिम रेलवे पर प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक का कार्यभार 25 अगस्त 2025 को ग्रहण किया था एवं लगभग एक वर्ष के कार्यकाल में इन्होंने कई उपलब्धियां एवं कीर्तिमान स्थापित किए हैं जैसे लैब का एनएबीएल एक्रीडिटेशन, सेंट्रल हॉस्पिटल में आरोग्यं कैफे एवं ओपीडी फार्मेसी तथा उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी मंडलों पर कुल 6 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की नियुक्ति सम्मिलित है। डॉक्टर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में उत्तर पश्चिम रेलवे के चिकित्सा विभाग में अनेक नवाचार अपनाए जिनका लाभ हजारों रेल कर्मचारियों, पेंशनरों एवं उनके परिजनों को मिला।

राजस्थान की प्रसिद्ध हवेलियों के लिए आने वाले सैलानियों का आवागमन हुआ और सुविधाजनक

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत हवेलियों के लिए प्रसिद्ध चूरू के रेलवे स्टेशन का हुआ है पुनर्विकास

सूत्र/रे.स.ब्यू - चूरू राजस्थान के ऐतिहासिक किले, भव्य भित्तिचित्रों वाली हवेलियाँ और वन्यजीव स्थलों के लिए प्रसिद्ध हैं। 1735 में बना चूरू किला इस बात के लिए मशहूर है कि घेराबंदी के दौरान यहाँ से चांदी के गोले दागे गए थे। यहां किया हवेलियां शेखावाटी शैली की बारीक चित्रकारी और सैकड़ों खिड़कियां हैं, राजस्थानी और यूरोपीय वास्तुकला की झलक और शानदार शीशे का काम और पेंटिंग्स हैं।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री अमित सुदर्शन के अनुसार राजस्थान की पारंपरिक हवेलियों को देखने चुरु आने वाले सैलानियों की सुविधा के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 19.68 करोड़ की लागत चूरू रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया गया है। चूरू स्टेशन के प्लेटफॉर्म, फुटओवर ब्रिज, स्टेशन, टिकट खिड़की प्रतीक्षालय, सर्कुलेटिंग एरिया आदि सभी को पुनर्विकसित किया गया है। चूरू स्टेशन पर भवन के समरूप में बड़े स्तर पर सुधार कार्य, स्टेशन की ओर आने-जाने वाले मार्ग में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग प्रावधान किया गया है। बाउंड्री वॉल, सर्कुलेटिंग एरिया में सौंदर्यकरण, दोपहिया, चौपहिया वाहनों के लिए अलग-अलग पार्किंग सुविधा, बुकिंग ऑफिस रिटायरिंग रूम आदि में सुधार, नए टॉयलेट ब्लॉक्स लगाए गए हैं।

उपरोक्त कार्यो के अलावा सौंदर्य वर्धन के लिए एलइडी लाइटिंग भी की गयी है। सभी सुविधाओं का दिव्यांगजनों तक पहुंच बनाने के लिए उपयुक्त साइनेज भी लगाया गया है । इस स्टेशन पर कला एवं संस्कृति का समन्वय करते हुए दीवारों एवं छतों पर आकर्षक पेंटिंग भी की गयी है । इसके अलावा यात्री सूचना प्रणाली में सुधार हेतु के कोच गाइडेंस डिस्प्ले बोर्ड, मल्टीलाइन डिस्पले बोर्ड्स, सिंगल लाइन डिस्प्ले बोर्ड, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, बड़े एलइडी स्क्रीन्स तथा जीपीएस आधारित डिजिटल क्लॉक भी लगाया गया है ।

स्टेशन की प्रकाश व्यवस्था, सुगम,निर्बाध एवं निरंतर तकनीकी रेल कार्यो के संचालन हेतु हरित ऊर्जा उत्पादन सोलर ऊर्जा प्लांट भी स्थापित किया जायेगा । इस हेतु लगभग 18 लाख की लागत से 40 किलोवाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। चूरू स्टेशन पर 10.68 करोड़ की लागत से 12 मीटर चौड़ा फुट ओवरब्रिज व लिफ्ट भी लगेगी । फुट ओवरब्रिज का 77% कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष कार्य शीघ्रता से पूरा किया जा रहा है।

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इस स्टेशन के पुनर्विकसित होने से यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, आवागमन सुगम होगा एवं पर्यटक भी लाभान्वित होंगे।

रेलवे के विकास में SQMS के चार मुख्य क्षेत्र - सुरक्षा, गुणवत्ता, गतिशीलता और कौशल पर विशेष जोर: सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर श्री विवेक कुमार गुप्ता

कानपुर-प्रयागराज रेलखंड का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की

सूत्र/रे.स.ब्यू - रेलवे बोर्ड के सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर श्री विवेक कुमार गुप्ता ने कानपुर प्रयागराज रेलखंड के निरीक्षण के क्रम में कानपुर सेंट्रल स्टेशन के पुनर्विकास कार्यों का गहन निरीक्षण किया तथा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के संकल्प सभागार में आयोजित बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए रेलवे के समग्र विकास के लिए SQMS – Safety, Quality, Mobility और Skills को चार प्रमुख Core Areas के रूप में रेखांकित किया।

निरीक्षण के दौरान उत्तर मध्य रेलवे के प्रमुख मुख्य इंजीनियर श्री ए.के. मनुवाल, प्रमुख मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर श्री दीपक कुमार सिन्हा, मंडल रेल प्रबंधक, प्रयागराज मंडल श्री रजनीश अग्रवाल सहित निर्माण विभाग एवं मंडल के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

श्री विवेक कुमार गुप्ता ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा आधुनिक एवं नवीनतम तकनीकों का अधिकाधिक उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्टेशन पुनर्विकास का उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक स्टेशन उपलब्ध कराना है। निर्माण कार्यों के दौरान यात्री सुविधाओं एवं यात्रियों की सुगम आवाजाही को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा निर्माण गतिविधियों के कारण यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। सभी निर्माण कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने तथा कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के अगले चरण में सदस्य इंफ्रास्ट्रक्चर ने कानपुर प्रयागराज रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलखंड पर चल रहे विभिन्न विकास एवं आधारभूत संरचना संबंधी कार्यों की प्रगति का अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। रेलखंड पर संरक्षा, समयबद्धता, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण तथा यात्री सुविधाओं से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए।

इसी क्रम में मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय के संकल्प सभागार में आयोजित बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री विवेक कुमार गुप्ता ने कहा कि रेलवे की कार्यप्रणाली और भविष्य की योजनाओं में Safety, Quality, Mobility और Skills के बीच बेहतर समन्वय एवं संतुलन आवश्यक है।

उन्होंने कहा कि Safety (संरक्षा) रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रत्येक परियोजना, निर्माण कार्य और परिचालन संबंधी निर्णय में निर्धारित संरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रक्रियाओं तथा डेटा आधारित विश्लेषण का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।

Quality (गुणवत्ता) के संबंध में उन्होंने कहा कि केवल किसी कार्य को पूरा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी गुणवत्ता और दीर्घकालिक उपयोगिता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। योजना बनाने से लेकर कार्य के क्रियान्वयन और उसके बाद रखरखाव तक प्रत्येक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

उन्होंने Mobility (गतिशीलता) को रेलवे की कार्यक्षमता का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए कहा कि रेल नेटवर्क की क्षमता, परिचालन दक्षता तथा यात्रियों और माल की निर्बाध आवाजाही को ध्यान में रखते हुए आधारभूत संरचना का विकास किया जाना चाहिए। विकास कार्यों की योजना बनाते समय वर्तमान आवश्यकताओं के साथ-साथ भविष्य की जरूरतों और उनके व्यापक प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाए।

माघ मेला-2027 की तैयारियों के संबंध में प्रयागराज मंडल में प्रथम आंतरिक समीक्षा बैठक सम्पन्न

सूत्र/रे.स.ब्यू - आगामी माघ मेला-2027 की व्यापक तैयारियों के क्रम में दिनांक 31 जुलाई, 2026 को प्रयागराज मंडल के संकल्प सभागार में प्रथम आंतरिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल रेल प्रबंधक, प्रयागराज श्री रजनीश अग्रवाल ने की। बैठक में अपर मंडल रेल प्रबंधक (सामान्य) श्री दीपक कुमार, अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) मो. मुबश्शिर वारिस सहित मंडल के सभी शाखा अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान माघ मेला-2027 के सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन हेतु विभिन्न विभागों द्वारा की जाने वाली तैयारियों एवं प्रस्तावित कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में अपर मंडल रेल प्रबंधक (सामान्य) श्री दीपक कुमार ने माघ मेला-2027 की विभागवार कार्ययोजना पर विस्तृत पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया। प्रस्तुतीकरण के दौरान संभावित यात्री भार, प्रमुख स्नान पर्वों पर भीड़ प्रबंधन, विशेष मेला ट्रेनों के संचालन, अतिरिक्त यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सेवाओं, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, बहुभाषी उद्घोषणा प्रणाली, संचार व्यवस्था तथा विभिन्न विभागों के मध्य प्रभावी समन्वय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सभी विभागों को समयबद्ध कार्ययोजना तैयार कर आवश्यक प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में प्रयागराज जंक्शन, नैनी, प्रयागराज छिवकी एवं सूबेदारगंज सहित प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अस्थायी यात्री आश्रयों की स्थापना, अतिरिक्त टिकट काउंटर, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (ATVM), दिशा-सूचक संकेतक, बहुभाषी उद्घोषणाएं, सीसीटीवी आधारित निगरानी, चिकित्सा सहायता केंद्र, स्वच्छता एवं पेयजल व्यवस्था तथा आपदा प्रबंधन की व्यापक तैयारियों पर विशेष बल दिया गया। साथ ही संबंधित विभागों को मेला प्रशासन एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ समयबद्ध समन्वय स्थापित कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में अवगत कराया गया कि माघ मेला-2027 का आयोजन 15 जनवरी, 2027 से 6 मार्च, 2027 तक प्रस्तावित है। इस अवधि में मकर संक्रांति (15 जनवरी), पौष पूर्णिमा (22 जनवरी), मौनी अमावस्या (06 फरवरी), बसंत पंचमी (11 फरवरी), माघी पूर्णिमा (20 फरवरी) तथा महाशिवरात्रि (06 मार्च) प्रमुख स्नान पर्व होंगे, जिनके दौरान प्रयागराज में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। इसे देखते हुए रेलवे द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते सुनिश्चित की जाएंगी।

चुनार से सीमेंट ढुलाई के लिए उत्तर मध्य रेलवे का डालमिया सीमेंट के साथ अनुबंध

सूत्र/रे.स.ब्यू - दिनांक 10 अगस्त, 2026 को प्रयागराज मंडल, उत्तर मध्य रेलवे ने माल ढुलाई को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुये चुनार स्थित डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड के साथ रेलवे द्वारा सीमेंट ढुलाई के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

अनुबंध पर डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड की ओर से श्री पी. सुडलाई मुथु, नेशनल लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस हेड तथा उत्तर मध्य रेलवे की ओर से श्रीमती शीरत फातिमा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक/फ्रेट ने अपर मंडल रेल प्रबंधक (सामान्य), श्री दीपक कुमार की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए।

उल्लेखनीय है कि डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड ने हाल ही में पूर्ववर्ती जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के चुनार स्थित सीमेंट संयंत्र का अधिग्रहण किया है तथा जून 2026 से यहां सीमेंट उत्पादन प्रारंभ किया गया है। संयंत्र के पुनः संचालन के साथ ही रेल मार्ग से सीमेंट एवं कच्चे माल के परिवहन को बढ़ावा देने के लिए रेलवे के साथ यह महत्वपूर्ण अनुबंध किया गया है।

अनुबंध के तहत अगस्त 2026 में लगभग 6-7 पूर्ण रेक (15,000 टन) सीमेंट का गाजीपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, चिलबिला सहित अन्य स्थानों के लिए रेल द्वारा परिवहन प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त, सितंबर 2026 से लगभग 10 पूर्ण रेक (26,000 टन) सीमेंट प्रतिमाह लोड करने की योजना है।

इसके साथ ही, सीमेंट उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता को पूरा करने हेतु लगभग 15 रेक क्लिंकर प्रतिमाह तथा लगभग 1-2 रेक जिप्सम प्रतिमाह मंगाए जाने की योजना है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि के साथ इन आवक रेकों की संख्या में भी वृद्धि होने की संभावना है।

डालमिया सीमेंट द्वारा चुनार से बड़े पैमाने पर रेल परिवहन शुरू किए जाने से प्रयागराज मंडल की माल ढुलाई आय में उल्लेखनीय वृद्धि, उद्योग को बेहतर एवं विश्वसनीय लॉजिस्टिक सुविधा तथा रेल यातायात में वृद्धि होने की उम्मीद है। साथ ही, यह पहल नए औद्योगिक ग्राहकों को रेल परिवहन से जोड़ने और मंडल में फ्रेट व्यवसाय के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

रेल की रफ्तार, जिंदगी की जीत: वंदे भारत के जरिए पहली बार पहुँचा जीवित हृदय

सूत्र/रे.स.ब्यू - भारतीय रेल ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से जीवित हृदय (Live Heart) का सफलतापूर्वक परिवहन किया। सूरत से अहमदाबाद तक हृदय को ट्रेन संख्या 20901 मुंबई सेंट्रल गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस से सुरक्षित एवं निर्धारित समय में पहुंचाया गया। इस हृदय का प्रत्यारोपण यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोल जी एंड रिसर्च सेंटर, अहमदाबाद में किया जाएगा।

यह अत्यंत संवेदनशील और समयबद्ध जीवनरक्षक अभियान भारतीय रेल, गुजरात राज्य पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) तथा चिकित्सा टीमों के बीच उत्कृष्ट समन्वय का उदाहरण रहा। हृदय को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से यू.एन. मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोल जी एंड रिसर्च सेंटर तक सुरक्षित एवं निर्बाध रूप से पहुंचाने के लिए RPF और गुजरात राज्य पुलिस द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। इसके माध्यम से अंग को निर्धारित समयसीमा के भीतर अस्पताल पहुंचाया गया, ताकि प्रत्यारोपण प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो।

मंडल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद, श्री वेद प्रकाश ने कहा, "यह भारतीय रेल के लिए अत्यंत गर्व और संतोष का क्षण है कि वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से एक जीवित हृदय को सूरत से अहमदाबाद तक सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से पहुंचाया गया। ऐसे जीवनरक्षक मिशन में समय का प्रत्येक क्षण महत्वपूर्ण होता है। भारतीय रेल, RPF, गुजरात राज्य पुलिस और चिकित्सा टीमों के बीच उत्कृष्ट समन्वय ने इस अभियान को सफल बनाया। किसी व्यक्ति का जीवन बचाने में भारतीय रेल की भूमिका निभाना हमारे लिए केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सेवा और मानवता का सर्वोच्च दायित्व है।"

वंदे भारत एक्सप्रेस की गति, समयपालन और विश्वसनीयता ने इस जीवनरक्षक अभियान को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारतीय रेल केवल यात्रियों और माल के परिवहन तक सीमित नहीं है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन एवं जीवनरक्षक स्वास्थ्य सेवाओं में भी महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभा रही है। इस ऐतिहासिक मिशन की सफलता में भारतीय रेल के विभिन्न विभागों, RPF, गुजरात राज्य पुलिस, चिकित्सकों, अंग प्रत्यारोपण समन्वयकों तथा सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। सभी एजेंसियों के बीच प्रभावी एवं त्वरित समन्वय के कारण यह चुनौतीपूर्ण जीवनरक्षक अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह ऐतिहासिक उपलब्धि भारतीय रेल की त्वरित, सुरक्षित और विश्वसनीय सेवाओं के साथ-साथ मानव जीवन की रक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है।

संपादकीय

देशभक्ति का एक रंग स्वच्छता भी-आइए रेल को स्वच्छ रखें

रेल समाचार ब्यूरो परिवार की ओर से सभी देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। 15 अगस्त हमें केवल आजादी का उत्सव मनाने का अवसर नहीं देता, बल्कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने की प्रेरणा भी देता है। आज स्वच्छता हमारे सामने एक महत्वपूर्ण चुनौती है और भारतीय रेलवे, जहाँ प्रतिदिन करोड़ों यात्री सफर करते हैं, इस जिम्मेदारी का एक अहम हिस्सा है। रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों को स्वच्छ बनाए रखना केवल रेलवे प्रशासन का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक यात्री की भी जिम्मेदारी है। हमारी छोटी-सी आदत बड़ा बदलाव ला सकती हैं यात्रा के दौरान कचरा निर्धारित स्थान पर डालना, स्टेशन और ट्रेन में गंदगी न फैलाना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुँचाना और स्वच्छता बनाए रखने में रेलकर्मियों का सहयोग करना। जिस रेलवे से हम रोज सफर करते हैं, उसे स्वच्छ रखना वास्तव में अपने देश और उसकी सार्वजनिक संपत्ति के प्रति सम्मान है। इस स्वतंत्रता दिवस आइए, तिरंगे को सलाम करने के साथ यह संकल्प भी लें कि हर रेल यात्रा में स्वच्छता और जिम्मेदारी को अपनी आदत बनाएँगे। क्योंकि स्वच्छ रेलवे केवल बेहतर यात्रा की पहचान नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक और जिम्मेदार भारत की पहचान भी है।

जय हिंद!

ठाणे स्टेशन पर स्वच्छता संबंधी शिकायत पर मध्य रेल की त्वरित कार्रवाई, प्रतीक्षालय स्थित मल्टी पर्पज स्टॉल सील, ठेकेदार पर ₹15,000 का जुर्माना

सूत्र/रे.स.ब्यू - ठाणे स्टेशन के प्रतीक्षालय में स्थित मल्टी पर्पज स्टॉल पर अस्वच्छ परिस्थितियों संबंधी सोशल मीडिया पर प्राप्त शिकायत का मध्य रेल ने तत्काल संज्ञान लिया। शिकायत की पुष्टि होने के बाद स्टॉल संचालित करने वाले ठेकेदार के विरुद्ध तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की गई। संबंधित स्टॉल को 7 दिनों के लिए सील कर दिया गया है तथा स्वच्छता एवं साफ-सफाई संबंधी मानकों का उल्लंघन करने पर ठेकेदार पर 15,000 का जुर्माना भी लगाया गया है।

मध्य रेल खानपान एवं वाणिज्यिक इकाइयों में अस्वच्छता के प्रति शून्य सहिष्णुता (जीरो टॉलरेंस) की नीति पर दृढ़ता से अमल कर रहा है। खाद्य सुरक्षा मानकों तथा स्वच्छता संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी स्टेशनों पर नियमित निरीक्षण किए जा रहे हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे स्वच्छता, खानपान सेवाओं अथवा यात्री सुविधाओं से संबंधित किसी भी समस्या की सूचना एवं अपना फीडबैक रेल मदद (RailMadad) के माध्यम से अवश्य दें।

यात्रियों की सुविधा हेतु प्रयागराज-सीकर-प्रयागराज साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा का संचालन

रेलवे द्वारा आगामी त्यौहारों पर अतिरिक्त यात्री यातायात को देखते हुए यात्रियो की सुविधा हेतु प्रयागराज-सीकर-प्रयागराज साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा का संचालन किया जा रहा है।

सूत्र/रे.स.ब्यू - उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री अमित सुदर्शन के अनुसार गाडी संख्या 04161, प्रयागराज-सीकर साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा दिनांक 10.08.26 से 30.11.26 तक (17 ट्रिप) प्रयागराज से प्रत्येक सोमवार को 17.10 बजे रवाना होकर मंगलवार को जयपुर स्टेशन पर 05.55 बजे आगमन व 06.00 बजे प्रस्थान कर 08.20 बजे सीकर पहुंचेगी। इसी प्रकार गाडी संख्या 04162, सीकर-प्रयागराज साप्ताहिक स्पेशल रेलसेवा दिनांक 11.08.26 से 01.12.26 तक (17 ट्रिप) सीकर से प्रत्येक मंगलवार को 15.25 बजे रवाना होकर जयपुर स्टेशन पर 17.15 बजे आगमन व 17.20 बजे प्रस्थान कर बुधवार को 08.50 बजे प्रयागराज पहुंचेगी। यह रेलसेवा मार्ग में भरवारी, फतेहपुर, गोविन्दपुरी, फफुंद, ईटावा, फतेहाबाद, आगराकेंट, भरतपुर, बांदीकुई, दौसा, खातीपुरा, जयपुर, ढेहर का बालाजी व रींगस स्टेशनों पर ठहराव करेगी।

भारतीय रेलवे ने बिहार के दानापुर और फतुहा के बीच पूर्वी मध्य रेलवे की 976 करोड़ रुपये की मल्टीट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी

सूत्र/रे.स.ब्यू - बिहार में रेल क्षमता को बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने पूर्वी मध्य रेलवे के 29 किलोमीटर लंबे दानापुर से फतुहा खंड पर 976 करोड़ रुपये की लागत से मल्टीट्रैक बिछाने की मंजूरी दी है। इस परियोजना से पटना रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त खंडों में से एक पर भीड़ कम होगी और यात्री एवं माल ढुलाई सेवाओं में भारी वृद्धि की संभावना बनेगी।

स्वीकृत कार्य में तीन घटक शामिल हैं। दानापुर और पटना के बीच तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी। राजेंद्र नगर और पटना साहिब के बीच तीसरी लाइन बिछाई जाएगी। पटना साहिब और फतुहा के बीच तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी। इन अतिरिक्त लाइनों से पटना क्षेत्र में यातायात जाम कम होगा, देरी कम होगी और समय की पाबंदी में सुधार होगा। परियोजना के संचालन के पहले वर्ष में, प्रतिदिन 22 अतिरिक्त यात्री ट्रेनें और 18 अतिरिक्त मालगाड़ियाँ चल सकेंगी। इससे प्रति वर्ष 52 लाख टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता भी बढ़ेगी।

यह परियोजना दिल्ली, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, पटना, किउल, भागलपुर, खन्ना और हावड़ा मार्ग पर चौगुनी रेल सुविधा शुरू करने की पहल का हिस्सा है। यह मार्ग भारतीय रेलवे के ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। मजबूत किया गया यह खंड बक्सर जिले के चौसा में बनने वाले 2120 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो भारी मात्रा में कच्चे माल की रेल ढुलाई पर निर्भर करेगा। इस मंजूरी से उच्च घनत्व वाले मार्गों पर क्षमता विस्तार करने, ऊर्जा और उद्योग के लिए रसद को मजबूत करने और बिहार के सामाजिक-आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए भारतीय रेलवे की प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है।

बरेका ने रचा नया इतिहास: एक माह में 65 विद्युत रेल इंजनों का रिकॉर्ड निर्माण

सूत्र/रे.स.ब्यू - बनारस रेल इंजन कारखाना (बरेका), वाराणसी ने एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ते हुए जुलाई 2026 के दौरान एक ही माह में रिकॉर्ड 65 विद्युत रेल इंजनों का निर्माण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह किसी भी वित्तीय वर्ष में एक माह के भीतर बरेका द्वारा किया गया अब तक का सर्वाधिक रेल इंजन उत्पादन है।

इस ऐतिहासिक उपलब्धि के अंतर्गत बरेका ने भारतीय रेल के लिए 44 डब्ल्यूएजी-9एचसी (WAG-9HC) मालवाहक विद्युत रेल इंजन, 13 डब्ल्यूएपी-7 (WAP-7) यात्री विद्युत रेल इंजन तथा 8 अमृत भारत विद्युत रेल इंजन का सफलतापूर्वक निर्माण किया। यह उपलब्धि बरेका की उत्कृष्ट उत्पादन क्षमता, अत्याधुनिक तकनीक तथा कर्मचारियों की समर्पित कार्य संस्कृति का सशक्त प्रमाण है।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व बरेका ने मार्च 2025 में एक माह के दौरान 61 विद्युत रेल इंजनों का निर्माण कर अपना सर्वोच्च मासिक उत्पादन रिकॉर्ड बनाया था, जिसे अब जुलाई 2026 में 65 इंजनों के निर्माण के साथ पीछे छोड़ दिया गया है। स्थापना काल से अब तक बरेका द्वारा कुल 11,445 रेल इंजनों का निर्माण किया जा चुका है, जिनमें 3,109 विद्युत रेल इंजन शामिल हैं। यह उपलब्धि भारतीय रेल के आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में बरेका की अग्रणी भूमिका को और सुदृढ़ करती है।

''मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड'' की अवधारणा को साकार करते हुए बरेका अब तक 11 देशों को 182 रेल इंजनों का निर्यात भी कर चुका है। इनमें मोजाम्बिक, म्यांमार, श्रीलंका, सूडान, तंजानिया, बांग्लादेश, माली सेनेगल, अंगोला, वियतनाम एवं मलेशिया देश शामिल हैं। इस ऐतिहासिक सफलता पर बरेका के महाप्रबंधक श्री आशुतोष पंत ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि प्रत्येक कर्मचारी की मेहनत, समर्पण, टीम भावना तथा उत्कृष्ट कार्य संस्कृति का परिणाम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बरेका वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित 468 विद्युत रेल इंजनों के उत्पादन लक्ष्य को भी निर्धारित समय से पूर्व तथा उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ प्राप्त करेगा।

बरेका की यह नई उपलब्धि न केवल बरेका की उत्कृष्ट उत्पादन क्षमता का परिचायक है, बल्कि भारतीय रेल के आधुनिकीकरण, 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान तथा भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है।

IRCTC बीटा वेबसाइट: एक आधुनिक और यूजर-फ्रेंडली डिजिटल बदलाव

सूत्र/रे.स.ब्यू - भारतीय रेलवे ने 15/07/2026 को बिल्कुल नई IRCTC बीटा वेबसाइट लॉन्च की, जो डिजिटल विकास की दिशा में एक अहम कदम है। रेल मंत्रालय के तहत एक नवरत्न PSU के तौर पर, IRCTC अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी और आधुनिक डिजाइन वाले प्लेटफॉर्म को लाकर यात्रियों के अनुभव को बेहतर बना रहा है। इससे पूरे भारत में लाखों यूजर्स के लिए रेलवे रिजर्वेशन की प्रक्रिया तेज, आसान और ज़्यादा भरोसेमंद हो गई है।

आसानी से यात्रा की योजना बनाने और बुकिंग करने की अपनी पुरानी खूबी को आगे बढ़ाते हुए, नए रूप में आए इस प्लेटफॉर्म का मकसद यूजर को एक आसान और बढ़िया अनुभव देना है। नए डिजाइन किए गए इंटरफेस का लुक शानदार और आधुनिक है, जो 'ग्लासम फिज़्म' जैसे ग्लोबल डिजाइन ट्रेंड्स से प्रेरित है। यह लॉगिन से लेकर टिकट कन्फर्मेशन तक एक आकर्षक और सुखद अनुभव देता है। इस अपग्रेड के साथ, यात्री अब जानकारी को ज़्यादा व्यवस्थित और आसानी से समझने लायक रूप में देख सकते हैं, जिससे उन्हें बुकिंग की प्रक्रिया में आसानी होती है।

नए प्लेटफॉर्म के बेहतर काम करने के तरीकों (वर्कफ़्लो) की वजह से बुकिंग की रफ्तार में साफ तौर पर सुधार हुआ है। इसकी तुलना महीने के पहले और दूसरे पखवाड़े के डेटा से की गई है। हाल के डेटा से पता चलता है कि 3-मिनट वाली तत्काल विंडो में पूरी होने वाली बुकिंग में 5% से ज़्यादा, 5-मिनट वाली तत्काल बुकिंग विंडो में 3% और 30-मिनट वाली विंडो में 2% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इससे पता चलता है कि यह प्लेटफॉर्म तेजी से बुकिंग का अनुभव देने में सक्षम है। पिछले महीनों की तुलना में जुलाई 2026 तक ऑनलाइन बुकिंग का हिस्सा भी बढ़कर 89-84% हो गया है।

इसके अलावा, ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम ने एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म देकर PRS (पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम) का बोझ काफी कम कर दिया है।

यूजर्स से मिले सुझावों के आधार पर, IRCTC ने बार-बार आने वाले CAPTCHA और परेशान करने वाले पॉप-अप मैसेज जैसी रुकावटों को काफी कम कर दिया है। नई वेबसाइट एक आसान और बिना रुकावट वाली डिजिटल यात्रा सुनिश्चित करती है, जिससे यात्री बिना किसी फालतू परेशानी के सिर्फ अपनी बुकिंग पर ध्यान दे पाते हैं।

नए डिजाइन किए गए इंटरफेस में यात्रा की अलग-अलग क्लासें जैसे स्लीपर, AC 3 टियर और AC 2 टियरेंकी उपलब्धता की जानकारी एक ही स्क्रीन पर मिल जाती है। इस सुविधा से यात्री एक नजर में ही अलग-अलग विकल्पों की तुलना कर सकते हैं, जिससे नेविगेशन की मेहनत कम होती है और वे तेजी से सही फैसले ले पाते हैं। IRCTC बीटा वेबसाइट का लॉन्च सिर्फ इसके लुक में बदलाव नहीं है। बल्कि यह ऑनलाइन रेलवे रिजर्वेशन के अनुभव को पूरी तरह से नए और बेहतर तरीके से तैयार करने की कोशिश है। यह प्लेटफॉर्म भविष्य के नए बदलावों के लिए एक मजबूत आधार बनाता है, जिसका मकसद रेलवे रिजर्वेशन को पहले से कहीं ज़्यादा तेज, आसान और भरोसेमंद बनाना है। वेबसाइट में बदलाव की प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और यूजर्स से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर, बेहतर अनुभव के लिए सिस्टम में लगातार सुधार किए जाएंगे।

मिर्जापुर-पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलखंड (64 RKM) पर 'कवच 4.0' का सफल कमीशनिंग कर रचा नया कीर्तिमान

सूत्र/रे.स.ब्यू - उत्तर मध्य रेलवे ने रेल संरक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए मिर्जापुर (समेत) पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (अपवर्जित) खंड के 64 रूट किलोमीटर पर KAVACH Version 4.0 (ट्रेन कोलिजन अव इडेंस सिस्टम) का सफल कमीशनिंग किया है। इस उपलब्धि के साथ उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल मे कमीशन किए गए नेटवर्क की कुल लंबाई बढ़कर 636 रूट किलोमीटर हो गई है। यह उपलब्धि भारतीय रेलवे के सुरक्षित, आधुनिक एवं तकनीक-आधारित रेल संचालन के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

'कवच' भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली (Automatic Train Protection System) है, जिसे ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए विकसित किया गया है। यह प्रणाली लाल सिग्नल पार करने (SPAD) की घटनाओं को रोकने, निर्धारित गति सीमा का पालन सुनिश्चित करने, संभावित टक्करों से सुरक्षा प्रदान करने तथा लोको पायलट को वास्तविक समय में आवश्यक परिचालन संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने का कार्य करती है। आधुनिक रेडियो संचार, माइक्रोप्रोसेसर एवं सेंसर आधारित यह प्रणाली इंजन, स्टेशन, सिग्नलिंग प्रणाली तथा ट्रेकसाइड उपकरणों के बीच निरंतर डेटा का आदान-प्रदान कर रेल संचालन को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाती है।

'कवच' प्रणाली में ट्रैक के बीच निर्धारित दूरी पर लगाए गए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टैग ट्रेन की सटीक स्थिति, दिशा और गति की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इंजन में स्थापित एंटेना इन टैगों को पढ़कर ट्रेन की वास्तविक लोकेशन का निर्धारण करते हैं। साथ ही, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी (UHF) रेडियो संचार प्रणाली के माध्यम से इंजन, स्टेशन एवं ट्रैकसाइड उपकरणों के बीच लगातार सूचनाओं का आदान-प्रदान होता रहता है। यदि चालक लाल सिग्नल पार करने का प्रयास करता है अथवा निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से ट्रेन चलाता है, तो 'कवच' पहले दृश्य एवं श्रव्य चेतावनी देता है और आवश्यकता पड़ने पर स्वतः ब्रेक लगाकर ट्रेन की गति नियंत्रित करता है। यह प्रणाली एक ही ट्रैक पर चल रही दो ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने में भी सक्षम है तथा घने कोहरे या कम दृश्यता की स्थिति में भी चालक को सिग्नल एवं गति प्रतिबंधों की सटीक जानकारी उपलब्ध कराकर सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करती है।

इससे पूर्व उत्तर मध्य रेलवे में चिपयाना-टूंडला (175 रूट किमी), टूंडला-पनकी धाम (207 रूट किमी) तथा कानपुर-प्रयागराज (छोड़कर) (190 रूट किमी) पर 'कवच 4.0' प्रणाली का सफल कमीशनिंग किया जा चुका था। इन चारों खंडों में कुल 572 रूट किलोमीटर पर 'कवच' संचालित है। अब मिर्जापुर (समेत)-पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन खंड के 64 रूट किलोमीटर के सफल कमीशनिंग के साथ चिपयाना (छोड़कर) से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन (प्रयागराज-मिर्जापुर को छोड़ कर) तक लगभग 636 रूट किलोमीटर का निरंतर 'कवच' संरक्षित रेलखंड तैयार हो गया है।

उत्तर मध्य रेलवे में शेष स्वीकृत रेलखंडों पर भी KAVACH का कार्य तीव्र गति से प्रगति पर है तथा चरणबद्ध तरीके से कमीशनिंग किया जा रहा है। इस परियोजना को महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे श्री नरेश पाल सिंह के मार्ग निर्देशन तथा प्रधान मुख्य सिग्नल एवं दूरसंचार इंजीनियर के नेतृत्व तथा सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, प्रयागराज मंडल, परियोजना, योजना, डिजाइन, ड्रॉइंग एवं फील्ड टीमों के समर्पित प्रयासों से सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस परियोजना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धियाँ भी हासिल की गईं। भारतीय रेलवे में पहली बार WAG-9 मालगाड़ी इंजन पर KERNEX निर्मित KAVACH का सफल कमीशनिंग किया गया। इसके साथ ही 09 इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग स्टेशनों पर KAVACH का सफल एकीकरण किया गया, जिनमें 07 Hitachi Electronic Interlocking तथा 02 Kyosan Electronic Interlocking स्टेशनों को प्रोटोकॉल कन्वर्टर के माध्यम से जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त RIU (Remote Interface Unit) के माध्यम से ऑटो सेक्शन सिग्नलिंग सूचना का भी सफल एकीकरण किया गया।

परियोजना के अंतर्गत आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग किया गया। संपूर्ण रेलखंड का ड्रोन, RSSI एवं RF सर्वे किया गया तथा ट्रैक पर 1,824 RFID टैग स्थापित किए गए। बेहतर संचार व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 03 नए 40 मीटर ऊंचे संचार टावर एवं संबंधित KAVACH अवसंरचना का निर्माण किया गया। इसके साथ ही 2x24-कोर बैकबोन ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) बिछाई गई तथा KAVACH भवनों एवं रिले रूम का निर्माण एवं विस्तार भी किया गया।

प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर मध्य रेलवे, OEM प्रतिनिधियों तथा ISA Italcertifier द्वारा संयुक्त रूप से व्यापक परीक्षण किए गए। इन परीक्षणों में SPAD रोकथाम, लूप लाइन गति नियंत्रण, SOS एवं विभिन्न फेल्योर मोड, RF एवं संचार विफलता परिदृश्य, STCAS कनेक्टिविटी, RFID रीडर परीक्षण तथा मोड ट्रांजिशन एवं एक्नॉलेजमेंट का सफल सत्यापन किया गया। इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस (15657/15658) तथा पुरुषोत्तम एक्सप्रेस (12801/12802) के माध्यम से ब्रेक आइसोलेटेड फील्ड ट्रायल भी सफलतापूर्वक संपन्न किए गए।

यह उपलब्धि दिल्ली-हावड़ा उच्च घनत्व रेल कॉरिडोर पर रेल सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने, परिचालन विश्वसनीयता बढ़ाने तथा उच्च गति से ट्रेनों के सुरक्षित संचालन को सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा 'कवच' के चरणबद्ध विस्तार से भारतीय रेलवे के 'मिशन रफ्तार' तथा सुरक्षित, आधुनिक और तकनीक-आधारित रेल परिचालन के लक्ष्य को नई गति मिल रही है।

तिरंगे की रोशनी में धड़कता देशप्रेम

80वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के रंगों में सजे रेलवे स्टेशनों की मनमोहक झलकियां

सूत्र/रे.स.ब्यू - देश 80वें स्वतंत्रता दिवस के गौरवपूर्ण अवसर को पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ मना रहा है। इस खास मौके पर भारतीय रेलवे के कई स्टेशन केसरिया, सफेद और हरे रंगों की रोशनी से जगमगा उठे, जिसने रात के आसमान में भी राष्ट्रीय पर्व की चमक बिखेर दी।
रोशनी से सजे इन रेलवे स्टेशनों की खूबसूरत तस्वीरें देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और मातृभूमि के प्रति सम्मान की भावना को जीवंत करती हैं। कहीं स्टेशन की ऐतिहासिक वास्तुकला तिरंगे की रोशनी में निखर उठी, तो कहीं आधुनिक रेलवे परिसर ने राष्ट्रीय ध्वज के रंगों के साथ स्वतंत्रता दिवस का संदेश दिया।
भारतीय रेलवे देश के करोड़ों लोगों को हर दिन जोड़ने वाली जीवनरेखा है। ऐसे में स्वतंत्रता दिवस पर स्टेशनों का तिरंगे के रंगों में जगमगाना देश की एकता, विविधता और साझा राष्ट्रीय भावना की खूबसूरत तस्वीर पेश करता है।

तिरंगे की शान में रंगा उत्तर मध्य रेलवे, धूमधाम से मनाया 80वां स्वतंत्रता दिवस

सूत्र/रे.स.ब्यू - उत्तर मध्य रेलवे प्रधान कार्यालय, प्रयागराज में 15 अगस्त 2026 को 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। महाप्रबंधक श्री नरेश पाल सिंह ने ध्वजारोहण किया और रेलवे सुरक्षा बल, भारत स्काउट एवं गाइड तथा सेंट जॉन एंबुलेंस ब्रिगेड की परेड का निरीक्षण किया। उत्कृष्ट कार्य के लिए 25 रेलकर्मियों और 6 संविदा सफाईकर्मियों सहित 31 कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।

समारोह में "हर घर तिरंगा वंदे मातरम" थीम पर विशेष प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर महाप्रबंधक एवं उत्तर मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्षा श्रीमती हिमा चौहान सिंह ने 12 दिव्यांग रेलकर्मियों को स्कूटी वितरित की।

अपने संबोधन में महाप्रबंधक ने बताया कि जुलाई 2026 तक सकल मूल अर्जन में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यात्री अर्जन में 15 प्रतिशत से अधिक, मालभाड़ा अर्जन में 10.5 प्रतिशत और टिकट जांच से अर्जन में 23.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। स्क्रैप बिक्री से 179 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड अर्जन हुआ। यात्रियों की सुविधा के लिए 4,656 ट्रिप ट्रेन ऑन डिमांड चलाई गई और 18 नई ट्रेनें शुरू की गई।

संरक्षा के क्षेत्र में 716 किलोमीटर रेलमार्ग पर कवच प्रणाली लगाई जा चुकी है और 303 रेल इंजनों में कवच उपकरण लगाए गए हैं। वहीं, 741 वातानुकूलित कोचों और 74 पावर कारों में फायर एवं स्मोक डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। उत्तर मध्य रेलवे ने पर्यावरण संरक्षण के तहत 23.9 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हैं। अप्रैल से जून 2026 के दौरान इनसे 6.95 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन हुआ, जिससे 4.50 करोड़ रुपये की राजस्व बचत हुई।

महाप्रबंधक ने बताया कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत 650 से अधिक बच्चों को सुरक्षित बचाया गया, जबकि ऑपरेशन नारकोस में 49 लोगों को गिरफ्तार कर 2.39 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की सामग्री बरामद की गई। कर्मचारियों के स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और कल्याण के लिए भी कई पहल की गई। समारोह को वेबकास्ट के माध्यम से रेलकर्मियों और अन्य लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी।

देशभक्ति के रंग में रंगा प्रयागराज मंडल

सूत्र/रे.स.ब्यू - प्रयागराज मंडल में 15 अगस्त 2026 को 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह गरिमापूर्ण वातावरण में मनाया गया। मंडल रेल प्रबंधक श्री रजनीश अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर रेलवे सुरक्षा बल, सिविल डिफेंस एवं भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की परेड का निरीक्षण किया। उत्कृष्ट कार्य के लिए 132 रेलकर्मियों को पुरस्कृत किया गया।

मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अब तक 2.68 करोड़ यात्रियों को परिवहन सुविधा दी गई, जिससे 629.58 करोड़ यात्री आय और 312.26 करोड़ माल आय प्राप्त हुई। मंडल का कुल अर्जन लगभग 1,019 करोड़ रहा। 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच 5,207 स्पेशल ट्रेनें संचालित की गई और मेल / एक्सप्रेस ट्रेनों की समयपालनता 87.89 प्रतिशत रही।

संरक्षा के क्षेत्र में 85 रेलकर्मियों को संरक्षा पुरस्कार दिए गए तथा 105 WAP-7 लोकोमोटिव में 100 प्रतिशत KAVACH फिटमेंट पूरा किया गया। RPF ने 'नन्हें फरिश्ते' के तहत 231 बच्चों को सुरक्षित बचाया, जबकि NARCOS के तहत 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 1.09 करोड़ के नशीले पदार्थ बरामद किए गए।

पर्यावरण के क्षेत्र में 1,572 kWp क्षमता के रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित किए गए और करीब 9.29 लाख पौधे लगाए गए। कर्मचारी कल्याण के तहत 2,271 पदोन्नतियां, 625 MACP मामलों का निस्तारण तथा 110 दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए और अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।

प्रयागराज-वेरावल विशेष रेलगाड़ी का झींझक एवं फफूँद स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव एवं समय में परिवर्तन

भारतीय रेल द्वारा अपने सम्मानित रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गाड़ी संख्या **04173/04174** प्रयागराज-वेरावल साप्ताहिक विशेष रेलगाड़ी का झिंझक एवं फफूंद स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव तथा गाड़ी सं. **04173** प्रयागराज-वेरावल विशेष रेलगाड़ी का इटावा स्टेशन पर दिनांक **13.08.2026** से **24.09.2026** तक समय में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

04173 प्रयागराज-वेरावल			04174 वेरावल-प्रयागराज	
वर्तमान समय	संशोधित समय	स्टेशन	वर्तमान समय	संशोधित समय
प्र.-10:10	कोई परिवर्तन नहीं	प्रयागराज	आ.-05:50	कोई परिवर्तन नहीं
-- --	13:48-13:50	झींझक	-- --	00:28-00:30
-- --	14:13-14:15	फफूँद	-- -	00:10-00:12
14:28-14:30	14:43-14:45	इटावा	22:58-23:00	कोई परिवर्तन नहीं

प्रयागराज सेः गाड़ी सं. 04173, प्रत्येक गुरूवार, दिनांकः 13.08.2026 से 24.09.2026
वेरावल सेः गाड़ी सं. 04174, प्रत्येक शुक्रवार,दिनांकः 14.08.2026 से 25.09.2026

उपरोक्त के अतिरिक्त ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के कारण गाड़ी सं. 04173 प्रयागराज-वेरावल विशेष रेलगाड़ी के मार्ग में परिवर्तन किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

गाड़ी सं.	स्टेशन से - स्टेशन तक	वर्तमान मार्ग	परिवर्तित मार्ग	प्रारंभिक स्टेशन से प्रभावी तिथि
04173	प्रयागराज-वेरावल	पालनपुर-महेसाना-विरमगाम	पालनपुर-भीलड़ी-महेसाना-विरमगाम	13.08.2026

नोटः ट्रेनों की समय-सारणी के सम्बन्धित जानकारी हेतु हेल्पलाइन 139 या Rail madad Mobile App या वेबसाइट railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग करें।

उत्तर मध्य रेलवे

North central railways @CPRONCR www.ncr.indianrailways.gov.in 1873/26 (PH)

रामनगर और देहरादून के बीच पहली सीधी एक्सप्रेस ट्रेन, उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों के बीच संपर्क उत्तम

सूत्र/रे.स.ब्यू - रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से रामनगर-देहरादून एक्सप्रेस की पहली सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही रामनगर और देहरादून को जोड़ने वाली पहली सीधी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अवसर पर उपस्थित हुए। यह नई ट्रेन इस क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है और यह उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों के बीच रेल संपर्क को काफी मजबूत करेगी। एक्सप्रेस ट्रेन हर बुधवार और शुक्रवार को चलेगी। ट्रेन संख्या 15310 रामनगर से सुबह 5:50 बजे प्रस्थान करेगी और दोपहर 12:40 बजे देहरादून पहुंचेगी। वापसी यात्रा में, ट्रेन संख्या 15309 देहरादून से दोपहर 15:55 बजे प्रस्थान करेगी और रात 23:30 बजे रामनगर पहुंचेगी। यह ट्रेन रास्ते में काशीपुर, रोशनपुर, पिपल्सना, मुरादाबाद, नजीबाबाद और हरिद्वार स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी सेकंड क्लास, एसी थर्ड क्लास, एसी चेयर कार, स्लीपर क्लास, सेकंड सिटिंग और जनरल सेकंड क्लास के कोच होंगे, जो विभिन्न श्रेणियों के यात्रियों के लिए आरामदायक यात्रा विकल्प प्रदान करेंगे। यह नई सेवा उत्तराखंड के नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जिलों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बिजनौर जिलों के निवासियों को लाभ पहुंचाएगी, जिनमें छात्र, किसान, व्यापारी और समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। इससे देहरादून और हरिद्वार के लिए सुविधाजनक एक ही दिन में कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे यात्री घर लौटने से पहले अपने आधिकारिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत कार्यों को पूरा कर सकेंगे। इस ट्रेन से क्षेत्र में पर्यटन और तीर्थयात्रा को बढ़ावा मिलने की भी आशा है। इससे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, रामनगर के पास कोसी नदी के बीच एक विशाल चट्टान पर स्थित गिरिजा देवी मंदिर और सीतामढ़ी/सीतावनी के प्राचीन धार्मिक स्थलों तक उत्तम कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा, हरिद्वार और देहरादून से आगे की कनेक्टिविटी के माध्यम से यात्रियों को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनात्री सहित चार धाम तीर्थयात्रा मार्ग तक पहुंचना अधिक सुविधाजनक होगा।

श्री वैष्णव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रामनगर-देहरादून एक्सप्रेस उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों के बीच रेल संपर्क को मजबूत करेगी। यह दोनों शहरों के बीच चलने वाली पहली सीधी एक्सप्रेस ट्रेन है और इससे उत्तराखंड के लोगों को तेज, अधिक सुविधाजनक और विश्वसनीय रेल संपर्क मिलने की आशा है। उन्होंने यह भी बताया कि हरिद्वार पर दबाव कम करने के लिए ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को फीडर स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें अतिरिक्त क्षमता सृजित करना और हरिद्वार और ऋषिकेश आने-जाने वाले यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना शामिल है।

श्री वैष्णव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उत्तराखंड में रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास तेजी से प्रगति कर रहा है। उन्होंने आगे बताया कि राज्य में 11 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है, जिनमें देहरादून, हरिद्वार जंक्शन, हर्रावाला, काशीपुर जंक्शन, किच्छा, कोटद्वार, रुड़की, काठगोदाम, लाल कुआं जंक्शन, रामनगर और टनकपुर शामिल हैं। रेल मंत्री ने कहा कि हरिद्वार और देहरादून स्टेशनों के पुनर्विकास की योजना इस प्रकार बनाई जा रही है कि गरीब और मध्यम वर्ग के यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भीड़भाड़ न बढ़े। रेल से जुड़ी अन्य पहलों के बारे में बताते हुए, श्री वैष्णव ने बताया कि हाल ही में शुरू की गई टनकपुर-नांदेड़ एक्सप्रेस को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इस इलाके में वंदे भारत सेवाएं भी अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि रामनगर-देहरादून एक्सप्रेस का शुभारंभ उत्तराखंड में रेल संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने नई रेल सेवा शुरू होने पर राज्य के लोगों को बधाई दी और इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने यह भी बताया कि उत्तराखंड में रेल संपर्क में हाल के वर्षों में काफी सुधार हुआ है और राज्य भर में कई नई रेल सेवाएं शुरू की गई हैं। श्री धामी ने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह उत्तराखंड के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और पर्यटन विकास के लिए जीवन रेखा साबित होगी।

इसके अलावा, श्री धामी ने बताया कि उत्तराखंड को रेलवे के लिए रिकॉर्ड 4,769 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जबकि राज्य में 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की रेलवे परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वयन के अधीन हैं। हरिद्वार में रेलवे विकास का जिक्र करते हुए श्री धामी ने कहा कि आगामी कुंभ महोत्सव को देखते हुए कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और ट्रेन सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई जा रही है।

रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला द्वारा बांग्लादेश रेलवे को निर्यात के लिए रेल डिब्बों का पहला रेक तैयार

सूत्र/रे.स.ब्यू - रेल डिब्बा कारखाना, कपूरथला, 12 अगस्त 2026 को बांग्लादेश रेलवे के लिए 19 एल एच बी ब्रॉड गेज रेल डिब्बों वाले पहले रेक के रोल-आउट के साथ एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने जा रहा है।

इस रेक में 03 AC स्लीपर कार, 03 AC चेयर कार, 11 नॉन-AC चेयर कार तथा 02 पावर कार शामिल हैं। इन रेल डिब्बों में कई विशिष्ट डिजाइन विशेषताओं एवं संशोधनों को शामिल किया गया है, जिनमें से अनेक LHB प्रकार के डिब्बों में पहली बार विकसित किए गए हैं।

इन कोचों को बांग्लादेश रेलवे की परिचालन एवं यात्री आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से कस्टमाइज किया गया है। इनमें यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई रिक्लाइनिंग चेयर, स्टेनलेस स्टील आर्मरेस्ट एवं स्टेनलेस स्टील फुटरेस्ट तथा सीटों को कई पोजीशन में रिक्लाइन करने की सुविधा प्रदान की गई है।

कोचों में यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अनेक आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें AC कोचों में पंखे, इंटीग्रेटेड CCTV सर्विलांस सिस्टम, पैसेंजर अलार्म सिस्टम, आंशिक रूप से खुलने वाली खिड़कियाँ, बेबी केयर रूम तथा प्रार्थना कक्ष शामिल हैं। विशिष्ट परिचालन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कोचों की रूफ स्ट्रक्चर को भी मजबूत किया गया है, ताकि पीक ट्रैफिक अवधि के दौरान छत पर यात्रियों के अतिरिक्त भार को सहन किया जा सके।

इन कोचों की एक प्रमुख तकनीकी विशेषता यूरोपीय मानक EN 15227 के अनुरूप Crashworthy Design Provisions का समावेश है। इसके लिए कार बॉडी शेल के व्यापक पुन:डिजाइन की आवश्यकता पड़ी, जिससे टक्कर की स्थिति में बेहतर प्रदर्शन तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन कोचों की विद्युत प्रणाली को भी विशेष रूप से 415 V ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि भारतीय रेल के कोचों में सामान्यत: 750 V प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

RCF और बांग्लादेश रेलवे के बीच सहयोग की शुरुआत 2015-16 में 120 LHB ब्रॉड गेज यात्री कोचों की सफल आपूर्ति के साथ हुई थी। इस सफल साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए बांग्लादेश रेलवे ने वर्ष 2024 में एक बार फिर RITES के माध्यम से RCF को सात विभिन्न प्रकार के 200 ब्रॉड गेज यात्री कोचों के निर्माण एवं आपूर्ति का प्रतिष्ठित ऑर्डर प्रदान किया।

ओंकारेश्वर रोड स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की सफल कमीशनिंग, यात्री सुविधाओं और सुरक्षित रेल परिचालन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

सूत्र/रे.स.ब्यू - इंदौर खंडवा गेज कन्वर्जन परियोजना के अंतर्गत ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन पर 13 अगस्त 2026 को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का सफलतापूर्वक कमीशनिंग किया गया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक, रतलाम, श्री कुंजीलाल मीना ने स्टेशन पर चल रहे निर्माण एवं संरक्षा संबंधी कार्यों का निरीक्षण किया। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का कमीशनिंग स्टेशन को यात्री ट्रेनों के परिचालन के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह आधुनिक प्रणाली रेल परिचालन में बेहतर समन्वय और संरक्षा को बढ़ावा देने में सहायक होती है। स्टेशन के विकास के साथ क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को मजबूती मिलने तथा यात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक और सुगम रेल यात्रा का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है।

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पर पत्थरबाजी का वायरल दावा फर्जी, उत्तर रेलवे ने किया खंडन

सूत्र/रे.स.ब्यू - सोशल मीडिया पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पर पत्थरबाजी का दावा करने वाला एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया गया कि हरियाणा में संचालित देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पर कुछ लोगों ने पत्थर फेंके। हालांकि, उत्तर रेलवे ने इस दावे को पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है।

रेलवे ने स्पष्ट किया कि वायरल वीडियो में दिखाई दे रही ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन नहीं है। अधिकारियों के अनुसार, वीडियो पुराना प्रतीत होता है और इसमें दिखाई गई ट्रेन WAG-12 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से संचालित होती है। रेलवे ने लोगों से अपील की है कि बिना पुष्टि के किसी भी वीडियो या जानकारी पर विश्वास न करें।

उत्तर रेलवे ने कहा कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन अपने निर्धारित समय के अनुसार नियमित रूप से संचालित हो रही है और उसकी सेवा में किसी प्रकार की बाधा नहीं आई है। रेलवे के अनुसार, वायरल वीडियो में दिखाई गई घटना का हाइड्रोजन ट्रेन से कोई संबंध नहीं है।

श्रीजगन्नाथ रथ यात्रा में उत्तर मध्य रेलवे की सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड ने पेश की मानव सेवा की मिसाल

सूत्र/रे.स.ब्यू - ओडिशा के पुरी में आयोजित 36वें नेशनल सर्विस कैंप एवं विश्व प्रसिद्ध श्रीजगन्नाथ रथ यात्रा 2026 के अवसर पर उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज की सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड के छह सदस्यीय दल ने अपनी उत्कृष्ट सेवाओं से मानव सेवा का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। 15 जुलाई से 17 जुलाई 2026 तक चले इस अभियान में दल ने ''मानव सेवा ही माधव सेवा'' के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए श्रद्धालुओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान की। इस सेवा अभियान की शुरुआत 15 जुलाई को पुरी के टाउन हॉल में आयोजित भव्य उद्घाटन समारोह से हुई, जिसमें ओडिशा के माननीय राज्यपाल, स्वास्थ्य मंत्री सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। उत्तर मध्य रेलवे के इस दल ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में सक्रिय सहयोग दिया। इसके बाद 15 से 17 जुलाई तक चली मुख्य रथ यात्रा के दौरान, जब पुरी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी, तब ग्रैंड ट्रंक रोड और मेडिकल कॉलेज क्षेत्र जैसे अत्यधिक व्यस्त स्थानों पर दल ने मोर्चा संभाला। इस दौरान लगातार हो रही भारी वर्षा के बावजूद स्वयंसेवकों ने पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ अपनी सेवाएँ जारी रखीं।

भारी भीड़ के दबाव के कारण श्रद्धालुओं के चोटिल होने, गिरने, फ्रैक्चर होने, बेहोशी और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं के मामलों में ब्रिगेड के सदस्यों ने तुरंत त्वरित प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया। तीन दिनों की इस कठिन सेवा अवधि में दल ने 300 से अधिक मरीजों को चिकित्सा सहायता दी।

रेलवे भूमि से 30 मीटर के भीतर किसी भी निर्माण हेतु रेलवे से एनओसी (NOC) लेना अनिवार्य

सूत्र/रे.स.ब्यू - मध्य रेलवे ने आम जनता को आगाह किया है कि रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों और यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशंस (UDCPR) के तहत रेलवे भूमि की सीमा से 30 मीटर के भीतर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले रेलवे प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना अनिवार्य है।

रेलवे प्रशासन के अनुसार, हालिया निरीक्षणों में प्रस्तावित रेलवे परियोजना के आसपास, विशेषकर रेलवे भूमि की सीमा से 30 मीटर के भीतर, बिना आवश्यक NOC के कई भवनों और अन्य संरचनाओं का निर्माण पाया गया है। रेलवे ने कहा कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान इस तरह के अनधिकृत निर्माणों में वृद्धि गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे रेलवे परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन में बाधा आ सकती है और भूमि अधिग्रहण, मुआवजे तथा पात्रता से जुड़े विवाद उत्पन्न हो सकते हैं।

भारतीय रेलवे ने उत्तर पूर्वी रेलवे के इज्ज़तनगर डिवीजन के 660 किलोमीटर मार्ग पर 295 करोड़ रुपये की लागत से कवच वर्जन 4.0 लगाने की मंजूरी दी

सूत्र/रे.स.ब्यू - भारतीय रेलवे ने उत्तर पूर्वी रेलवे (NER) के इज्जतनगर डिवीजन के 660 किलोमीटर मार्ग पर 295 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कवच वर्जन 4.0 प्रावधान को मंजूरी दे दी है। इस कार्य को ''भारतीय रेलवे के शेष खंडों पर लॉन्ग-टर्म इवोल्यूशन (LTE) के संचार बैकबोन के साथ कवच उपलब्ध कराने'' नामक व्यापक परियोजना के तहत मंजूरी दी गई है। कवच भारत की स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (ATP) प्रणाली है, जिसे ट्रेनों की आवाजाही की निरंतर निगरानी के माध्यम से सिग्नल पास्ड एट डेंजर (SPAD) की घटनाओं और ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्रणाली आवश्यकता पड़ने पर स्वचालित रूप से ब्रेक लगाती है, ट्रेनों को अधिकतम अनुमत गति पर सुरक्षित रूप से चलने में सक्षम बनाती है, परिचालन विश्वसनीयता में सुधार करती है और घने कोहरे जैसी प्रतिकूल मौसम स्थितियों में भी सुरक्षित ट्रेन संचालन में सहायता करती है।

स्वीकृत कार्य में उत्तर पूर्वी रेलवे के इज्ज़तनगर डिवीजन के शेष खंड शामिल हैं। कवच संस्करण 4.0 के प्रावधान से चिन्हित रेलवे खंडों पर सुरक्षा अवसंरचना को और मजबूत किया जाएगा।

गुजरात के गेरतपुर-अहमदाबाद खंड पर 153 करोड़ रुपये की लागत से 4 लेन की आरओबी के निर्माण को मंजूरी

सूत्र/रे.स.ब्यू - गुजरात में सड़क यातायात की सुरक्षित और सुगम आवाजाही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, भारतीय रेलवे ने पश्चिमी रेलवे के गेरतपुर-अहमदाबाद खंड पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 305 पर चार लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के लिए 153 करोड़ रुपये की लागत स्वीकृत की गई है।

यह परियोजना पश्चिमी रेलवे के चल रहे व्यापक कार्य के तहत स्वीकृत की गई है, जिसमें सड़क के ऊपर और नीचे पुलों का निर्माण, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी में सुधार और सड़क के ऊपर और नीचे पुलों का पुनर्निर्माण शामिल है।

यह पुल घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र में स्थित है, जिसके लिए लंबे अप्रोच और एक बड़े निर्माण की आवश्यकता है। रेलवे पुल की कुल लंबाई 106 मीटर होगी। इसमें 53 मीटर के दो संयुक्त गर्डर शामिल होंगे। इसके बाद 150 मीटर का वायडक्ट बनेगा। रेलवे अप्रोच की लंबाई 595 मीटर होगी।

यात्रियों के लिए सुरक्षित और तेज आवागमन

नए ओवरब्रिज के बनने से सड़क उपयोगकर्ताओं को लेवल क्रॉसिंग पर इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे रेलवे लाइन के ऊपर से वाहनों का आवागमन चौबीसों घंटे निर्बाध रहेगा। क्षेत्र के सड़क उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित आवागमन, कम समय में यात्रा और क्रॉसिंग पर भीड़भाड़ से राहत मिलेगी।

केंद्रीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने केंद्र से संत गजानन महाराज के 150वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करने का आग्रह किया

सूत्र/रे.स.ब्यू - केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने भारत सरकार से पूज्य संत श्री संत गजानन महाराज के 150वें प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में 150 रुपये का स्मारक सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का आग्रह किया है।

श्री जाधव ने वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत को संबोधित पत्रों में संबंधित मंत्रालयों से प्रस्ताव पर विचार करने और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया। अपने पत्रों में लिखा कि श्री संत गजानन महाराज फरवरी 1878 में महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के शेगांव में पहली बार प्रकट हुए थे। वे महाराष्ट्र और भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में एक पूजनीय स्थान रखते हैं। तब से, शेगांव भारत के प्रमुख तीर्थ केंद्रों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। शेगांव में देश और विदेश से श्रद्धालु आते हैं।

श्री जाधव ने कहा कि संत गजानन महाराज का जीवन और शिक्षाएं आध्यात्मिकता, भक्ति, करुणा, निस्वार्थ सेवा और मानव कल्याण के संदेश के माध्यम से पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। संत के जीवन और शिक्षाओं का विवरण पूज्यनीय धार्मिक ग्रंथ श्री गजानन विजय में मिलता है। इस ग्रंथ का उनके अनुयायियों के बीच विशेष स्थान है।

मंत्री जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, सामाजिक कल्याण और मानव सेवा के क्षेत्रों में श्री गजानन महाराज संस्थान, शेगांव के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे शेगांव की आध्यात्मिक और सामुदायिक सेवा के केंद्र के रूप में पहचान और मजबूत होती है।

आयुष मंत्रालय और इंडियाएआई ने पारंपरिक चिकित्सा के भविष्य के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने की दिशा में समझौता किया

सूत्र/रे.स.ब्यू - आयुष मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडियाएआई ने आयुष प्रणाली तंत्र को मजबूत करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में आयुष क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) संचालित नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी डॉ. कविता जैन और इंडियाएआई मिशन के मुख्य परिचालन अधिकारी और एमईआईटीवाई के संयुक्त सचिव श्री सुदीप श्रीवास्तव ने आयुष मंत्रालय और इंडियाएआई के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

आयुष प्रणाली तंत्र में शोध और नवाचार को मजबूत करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की क्षमता का उल्लेख करते हुए डॉ. कविता जैन ने कहा कि आयुष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण साक्ष्य-आधारित अनुसंधान, ज्ञान प्रबंधन और नवाचार के नए द्वार खोलेगा। उन्होंने कहा कि इंडियाएआई के साथ सहयोग से शोध, औषधीय पौधों, औषधि प्रशासन और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में उन्नत एआई क्षमताओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी। इससे आयुष प्रणाली तंत्र अधिक प्रौद्योगिकी-संचालित और भविष्य के लिए तैयार हो जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सुदीप श्रीवास्तव ने भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी के एकीकरण के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि इंडियाएआई और आयुष मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन एआईकोश को पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल डेटासेट से समृद्ध करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह एआई-सक्षम नवाचार के माध्यम से पारंपरिक चिकित्सा विज्ञान के शोधकर्ताओं और चिकित्सकों को सशक्त बनाएगा।

आयुष ग्रिड के ओएसडी श्री नमन गोयल ने बताया कि अपनी उभरती प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत आयुष ग्रिड आयुष क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन को गति देने के लिए एआई-आधारित प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित समझौता ज्ञापन आयुष प्रणाली तंत्र में एआई को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी।

यह सहयोग परंपरागत ज्ञान और आधुनिक एआई क्षमताओं को एक साथ लाकर प्रौद्योगिकी-आधारित आयुष प्रणाली तंत्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह साझेदारी अनुसंधान, क्षमता निर्माण, औषधीय पौधों और औषधि प्रशासन सहित प्रमुख आयुष क्षेत्रों में एआई को अपनाने और उसके अनुप्रयोग को गति देने पर केंद्रित होगी।

इस सहयोग के तहत, आयुष मंत्रालय एआई कोश प्लेटफॉर्म से जुड़ेगा जिससे डेटासेट, मेटाडेटा, एआई मॉडल, टूलकिट और प्रासंगिक उपयोग मामलों सहित योग्य स्वास्थ्य अनुसंधान सामग्री साझा करना संभव होगा। उम्मीद है कि यह एकीकरण आयुष क्षेत्र के लिए एआई समाधानों के बेहतर सहयोग, नवाचार और जिम्मेदार विकास को बढ़ावा देगा।

यह समझौता ज्ञापन परिभाषित सेवा-स्तर समझौतों के अधीन, इंडियाएआई पहल के माध्यम से रियायती दरों पर जीपीयू-आधारित और उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग अवसंरचना तक पहुंच प्रदान करने में सहायक होगा। उन्नत कंप्यूटिंग अवसंरचना तक पहुंच से महत्वपूर्ण अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य सेवा एवं पारंपरिक चिकित्सा में परिष्कृत एआई अनुसंधान एवं अनुप्रयोगों के विस्तार में सहायता मिलने की उम्मीद है।

सीसीआरएएस-एनआईआईएमएच ने चिकित्सा पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए सेवाधी संग्रहालय और इंडोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

केरल की चिकित्सा विरासत के संरक्षण और दस्तावेजीकरण में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन

सूत्र/रे.स.ब्यू - भारत की पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान विरासत के संरक्षण, प्रलेखन और व्यापक पहुंच के लिए आयुष मंत्रालय के आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सीसीआरएएस) के हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान (एनआईआईएमएच), ने चिकित्सा पांडुलिपियों के अपने संग्रह के व्यवस्थित डिजिटलीकरण और एक वर्णनात्मक सूची तैयार करने के लिए केरल के कोट्टायम जिले के कुमारनल्लूर स्थित सेवाधी संग्रहालय और इंडोल जिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

कुमारनल्लूर ऊरनमा देवस्वम द्वारा संचालित सेवाधी संग्रहालय और इंडोल जिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने मंदिर अभिलेखों सहित 30,000 से अधिक पांडुलिपियों का विशाल संग्रह संरक्षित किया है। यह समझौता ज्ञापन केरल की समृद्ध चिकित्सा और बौद्धिक परंपराओं से जुड़े बहुमूल्य पांडुलिपि संसाधनों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगात्मक पहल का प्रतीक है।

संस्था द्वारा संरक्षित पांडुलिपि संग्रह में आयुर्वेद और पारंपरिक ज्ञान के संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित दुर्लभ और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण रचनाएँ शामिल हैं। इनमें से कई पांडुलिपियाँ भारतीय ज्ञान प्रणाली में चिकित्सा संबंधी विचारों, उपचार पद्धतियों, औषधियों, निदान संबंधी अवधारणाओं और विद्वतापूर्ण परंपराओं के विकास को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

सहयोगात्मक ढांचे के तहत, सीसीआरएएस-एनआईआईएमएच सैकड़ों चिकित्सा पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण और उनके वर्णनात्मक सूची तैयार करने के लिए तकनीकी और विद्वतापूर्ण विशेषज्ञता प्रदान करेगा। डिजिटलीकरण उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल प्रतियां बनाने में सहायक होगा, जिससे पांडुलिपियों के दीर्घकालिक संरक्षण में योगदान मिलेगा और दुर्लभ तथा ऐतिहासिक रूप से मूल्यवान सामग्रियों को भौतिक रूप से संभालने की आवश्यकता कम हो जाएगी।

इस पहल का प्रमुख घटक एक व्यापक वर्णनात्मक सूची तैयार करना होगा। इस सूची में आयुष पांडुलिपि उन्नत भंडार के प्रारूप के अनुसार, शीर्षक, लेखक, विषय, लिपि, भाषा, सामग्री, भौतिक आयाम, पृष्ठ विवरण, स्थिति, उत्पत्ति और अन्य प्रासंगिक विशेषताओं सहित आवश्यक ग्रंथसूची और पांडुलिपि संबंधी जानकारी दर्ज की जाएगी। इस प्रकार के व्यवस्थित प्रलेखन से पांडुलिपियों की खोज क्षमता बढ़ेगी और विद्वानों और शोधकर्ताओं को भविष्य के शोध के लिए प्रासंगिक प्राथमिक स्रोतों की पहचान करने और उन तक पहुंचने के लिए विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होगी।

पारंपरिक दवाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए "वन हर्ब, वन स्टैंडर्ड": केंद्रीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव

सूत्र/रे.स.ब्यू - फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी (आयुष मंत्रालय) और इंडियन फार्माकोपिया कमीशन (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) ने "वन हर्ब, वन स्टैंडर्ड" पहल के कार्यान्वयन के लिए अपने समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया।

यह समझौता ज्ञापन पीसीआईएमएंडएच के निदेशक (प्रभारी) डॉ. कौस्तुभ उपाध्याय और डॉ. वी. कलाइसैल्वन, सचिव-सह-वैज्ञानिक निदेशक, आईपीसी द्वारा कर्तव्य भवन, नई दिल्ली में माननीय केन्द्रीय आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव एवं आयुष मंत्रालय के सचिव, वैद्य राजेश कोटेचा की उपस्थिति में एक-दूसरे को प्रदान किया गया।

वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियोंआयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी और होम्योपैथीदेश की समृद्ध ज्ञान परंपराओं और औषधीय पौधों की विरासत का अभिन्न अंग हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पारंपरिक दवाओं की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए वैज्ञानिक रूप से विकसित मानकों के माध्यम से दवाओं और औषधीय पौधों की गुणवत्ता, शुद्धता और मानकीकरण सुनिश्चित करना आवश्यक है।

श्री प्रतापराव जाधव ने "वन हर्ब, वन स्टैंडर्ड" दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। इसका उद्देश्य विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में उपयोग किए जाने वाले एक ही औषधीय पौधे के लिए एक समान, स्पष्ट, वैज्ञानिक और विश्वसनीय मानक स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि समन्वित मानकों से हितधारकों के बीच संभावित भ्रम को दूर करने में मदद मिलेगी और औषधीय पौधों के मानकीकरण के लिए एक अधिक सुदृढ़ एवं समन्वित रूपरेखा स्थापित होगी।

श्री जाधव ने कहा कि इस सहयोग के तहत तैयार किए गए मोनोग्राफ में भारतीय मानकों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक मानकों के अनुरूप भारतीय मानकों को मजबूत करने से भारतीय औषधीय पौधों और उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ेगी और उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज़्यादा स्वीकार्यता मिलेगी। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि समान और स्पष्ट गुणवत्ता मानक होने से निर्माताओं, निर्यातकों, परीक्षण प्रयोगशालाओं, नियामक संस्थानों तथा अन्य हितधारकों के लिए प्रक्रियाएं अधिक सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनेंगी तथा व्यापार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री श्री जाधव ने इस पहल के लिए पीसीआईएमएंडएच और आईपीसी के नेतृत्व, वैज्ञानिकों और अधिकारियों की लगातार कोशिशों की प्रशंसा की। उन्होंने भरोसा जताया कि तीन साल के लिए हुए नए समझौता ज्ञापन से औषधीय पौधों के मानकीकरण को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि अलग-अलग मंत्रालयों के बीच सहयोग यह दिखाता है कि मंत्रालयों और संस्थानों की मिली-जुली कोशिशें औषधीय पौधों और पारंपरिक दवाओं के मानकीकरण को कैसे मजबूत कर सकती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह पहल भारत की समृद्ध जैव-विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत को बचाने में मदद करेगी, साथ ही औषधीय पौधों, पारंपरिक दवाओं और उनके गुणवत्ता मानकों के मामले में एक भरोसेमंद वैश्विक मानक-निर्धारक के तौर पर भारत की स्थिति को मजबूत करेगी।

नवीनीकृत समझौता ज्ञापन के तहत मंत्रालयों के बीच सहयोग अगले तीन वर्ष तक जारी रहेगा। इसका उद्देश्य आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी और होम्योपैथी चिकित्सा प्रणालियों में उपयोग होने वाले औषधीय पौधों से मिलने वाली एकल औषधियों के लिए एक समान, भरोसेमंद और वैज्ञानिक रूप से मजबूत गुणवत्ता मानक विकसित करना है। नवीनीकृत साझेदारी के तहत तैयार किए जाने वाले मोनोग्राफ में भारतीय मानकों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता संबंधी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। इससे भारतीय मानकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप मजबूत करने में मदद मिलेगी तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय औषधीय पौधों और उत्पादों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता में वृद्धि होगी।

यह सहयोग 2022 में शुरू किए गए उस समझौता ज्ञापन पर आधारित है जिसका मकसद ''वन हर्ब, वन स्टैंडर्ड'' परिकल्पना को बढ़ावा देना और उसे सुगम बनाना था। इसके तहत पहले चरण में औषधीय पौधों के 50 मोनोग्राफ सफलतापूर्वक तैयार किए गए थे। यह नई साझेदारी इस रूपरेखा को और आगे बढ़ाएगी। इसके तहत अलग-अलग पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में एक ही औषधीय पौधे के लिए मानकों में तालमेल बिठाया जाएगा, जिससे हितधारकों के बीच अस्पष्टता कम होगी और मानकीकरण का एक मजबूत और समन्वित तंत्र विकसित होगा। पीसीआईएमएंडएच और आईपीसी की वैज्ञानिक और मानक-निर्धारण से जुड़ी विशेषज्ञता को एक साथ लाकर, यह पहल गुणवत्ता आश्वासन को सुदृढ़ करेगी, व्यापार सुगमता में मदद करेगी और भारत की समृद्ध जैव-विविधता व पारंपरिक चिकित्सा विरासत को सुरक्षित रखने में योगदान देगी। साथ ही, इससे ग्लोबल फार्मास्युटिकल मानकीकरण में भारत की स्थिति भी बेहतर होगी।

समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण, वनस्पति मानकीकरण के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाकर भारत की पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में वैज्ञानिक उत्कृष्टता, गुणवत्ता, विश्वसनीयता और वैश्विक स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के प्रति दोनों संस्थानों की निरंतर प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि करता है। इस साझेदारी से औषधीय पौधों, पारंपरिक दवाओं और उनके गुणवत्ता मानकों के लिए एक विश्वसनीय वैश्विक मानक-निर्धारक के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है।

चित्रकूट के लिए सीधी रेल कनेक्टिविटी मजबूत करने के उद्देश्य से चित्रकूटधाम कर्वी-कानपुर सेंट्रल और प्रतापगढ़-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस सेवाओं के विलय को मंजूरी

सूत्र/रे.स.ब्यू - भारतीय रेलवे ने यात्री सुविधा बढ़ाने और ट्रेन परिचालन को अधिक सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 14109/14110 चित्रकूटधाम कर्वी-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस और 14123/14124 मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़-कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस के विलय को मंजूरी दी है। विलय के बाद यह सेवा 14123/14124 मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़-चित्रकूटधाम कर्वी एक्सप्रेस के रूप में संचालित होगी।
इस विलय से मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ और चित्रकूटधाम कर्वी के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। साथ ही, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ क्षेत्र और चित्रकूट सहित अन्य महत्वपूर्ण गंतव्यों के बीच संपर्क भी मजबूत होगा।

24 कोच की ट्रेन से बढ़ेगी यात्री क्षमता

इस विलय से होने वाले परिचालन लाभों के तहत संयुक्त ट्रेन सेवा की यात्री क्षमता बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में 12 कोच वाली ट्रेन को बढ़ाकर 24 कोच किया जाएगा। इससे उपलब्ध सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और कानपुर-प्रतापगढ़ रेलखंड पर भीड़भाड़ तथा यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। बढ़ी हुई क्षमता से कानपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रतापगढ़ तथा मार्ग के अन्य स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी।

चित्रकूट और प्रतापगढ़/लखनऊ क्षेत्र के बीच बेहतर सीधी कनेक्टिविटी

विलय के बाद यह सेवा चित्रकूट और लखनऊ-प्रतापगढ़ क्षेत्र के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। यात्रियों को कानपुर सेंट्रल पर ट्रेन बदलने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे यात्रा अधिक सुविधाजनक होगी।
इससे विशेष रूप से तीर्थयात्रा, पर्यटन, शिक्षा, रोजगार और अन्य उद्देश्यों से चित्रकूट, प्रतापगढ़ तथा लखनऊ क्षेत्र के महत्वपूर्ण धार्मिक एवं क्षेत्रीय केंद्रों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा।

प्रमुख स्टेशनों के बीच बेहतर संपर्क

विलय की गई सेवा मार्ग में आने वाले महत्वपूर्ण स्टेशनों पर अपनी सेवाएं जारी रखेगी। इनमें मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़, चिलबिला, मां चंद्रिका देवी धाम अंतू, अमेठी, गौरीगंज, काशिमपुर, जायस, फुरसतगंज, रायबरेली, हरचंदपुर, बछरावां, निगोहां, लखनऊ, मानक नगर, उन्नाव, कानपुर सेंट्रल, भीमसेन, कठारा रोड, पनारा, घाटमपुर, हमीरपुर रोड, यमुना साउथ बैंक, भरुआ सुमेरपुर, रागौल, बांदा, अतर्रा और चित्रकूटधाम कर्वी शामिल हैं।
नई विलय की गई सेवा उत्तर प्रदेश में यात्री कनेक्टिविटी को मजबूत करने, महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों तक पहुंच बेहतर बनाने और रेलवे संसाधनों के अधिक प्रभावी उपयोग में मदद करेगी। इससे बुंदेलखंड और अवध के बीच एक निर्बाध रेल गलियारा स्थापित होगा। यह सेवा चित्रकूट को राज्य की राजधानी लखनऊ तथा प्रतापगढ़ से सीधी रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। साथ ही, ट्रेन में कोचों की संख्या 12 से बढ़ाकर 24 किए जाने से यात्री वहन क्षमता दोगुनी हो जाएगी और यात्रियों को किफायती दरों पर बेहतर रेल सेवा उपलब्ध होगी। चित्रकूट की तीर्थयात्रा और पर्यटन को बढ़ावा देने के अलावा, यह सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार, व्यापार और प्रशासनिक कार्यों के लिए यात्रा करने वाले लोगों के लिए भी कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। साथ ही, उपलब्ध ट्रेन परिचालन संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग सुनिश्चित होगा।

मध्य प्रदेश में इटारसी-मदन महल के बीच दैनिक पैसेंजर सेवा शुरू करने की स्वीकृति इटारसी-जबलपुर क्षेत्र के यात्रियों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए दैनिक सेवा

सूत्र/रे.स.ब्यू -भारतीय रेलवे ने दैनिक ट्रेन संख्या 51673/51674 इटारसी-मदन महल पैसेंजर की शुरुआत को स्वीकृति दे दी है। यह मध्य मध्य प्रदेश में रेल संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नई यात्री सेवा इटारसी और जबलपुर (मदन महल) के बीच रेल संपर्क को मजबूत करेगी, और प्रमुख मध्यवर्ती स्टेशनों पर यात्रियों के लिए यात्रा के बेहतर विकल्प भी उपलब्ध कराएगी। ट्रेन संख्या 51673 इटारसी-मदन महल पैसेंजर इटारसी जंक्शन से 11:40 बजे चलेगी और 16:45 बजे मदन महल पहुंचेगी। वापसी में, ट्रेन संख्या 51674 मदन महल-इटारसी पैसेंजर मदन महल से 17:50 बजे चलेगी और 22:55 बजे इटारसी जंक्शन पहुंचेगी। यह दैनिक पैसेंजर सेवा लगभग 5 घंटे 5 मिनट में 242 किमी की दूरी तय करेगी। ट्रेन बागरा तवा, सोहागपुर, पिपरिया, बनखेड़ी, सालीचौका रोड, गाडरवारा, करेली, नरसिंहपुर और श्रीधाम में वाणिज्यिक ठहराव करेगी, जिससे इन स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिलेगी।
इटारसी-मदन महल पैसेंजर सेवा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जोड़ने के बजाय क्षेत्रीय संपर्क (कनेक्टिविटी) के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह सेवा जबलपुर और इटारसी के दो प्रमुख रेलवे नोड्स को जोड़ने के साथ-साथ, जबलपुर-नर्मदापुरम बेल्ट के बीच पड़ने वाले कस्बों और छोटे स्टेशनों तक दैनिक आधार पर किफायती यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। यह सेवा विशेष रूप से मध्यम-वर्ग, अनारक्षित और कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए है। इस तरह की सेवा एक महत्वपूर्ण फीडर/डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी करती है, जिससे रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार और तीर्थ स्थलों तक पहुंच आसान हो जाती है और इटारसी से भारत के अन्य हिस्सों के प्रमुख गंतव्यों के लिए आगे की यात्र की सुविधा भी मिलती है।

यात्रियों की थाली की गुणवत्ता पर भारतीय रेल की सख्ती, 5.13 करोड़ का जुर्माना, 54 नोटिस और 6 अनुबंध समाप्त

सूत्र/रे.स.ब्यू - केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी जानकारी बताया कि भारतीय रेल यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य गुणवत्ता एवं स्वच्छता व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रही है। पिछले तीन वर्षों में प्राप्त शिकायतों के आधार पर आईआरसीटीसी ने खाद्य गुणवत्ता और स्वच्छता उल्लंघनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 5.13 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए, 6 अनुबंध समाप्त किए और दोषी लाइसेंसधारियों पर प्रतिबंध लगाया। प्रतिबंधित लाइसेंसधारियों की सूची आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है। भारतीय रेल औसतन प्रतिवर्ष लगभग 58 करोड़ थाली भोजन परोसती है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतें औसतन केवल 0.0008 प्रतिशत हैं।
खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित बेस किचन से भोजन की आपूर्ति, चिन्हित स्थानों पर आधुनिक बेस किचन की स्थापना तथा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया की बेहतर निगरानी के लिए बेस किचन में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। खाद्य उत्पादन में लोकप्रिय एवं ब्रांडेड कच्चे माल के उपयोग के साथ मुख्य रसोईघरों में खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। ट्रेनों में आईआरसीटीसी के पर्यवेक्षक भी खानपान सेवाओं की निगरानी करते हैं।
यात्रियों के लिए खाद्य पैकेटों पर क्यूआर कोड की व्यवस्था खाद्य सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने में सहायक होगी। इसके माध्यम से पैकेट की पैकिंग तिथि, लाइसेंसधारक का नाम और एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर जैसी जानकारी उपलब्ध होगी। बेस किचन और पैंट्री कारों में नियमित गहन सफाई एवं समय-समय पर कीट नियंत्रण भी किया जाता है। खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए एफएसएसएआई का अनिवार्य प्रमाणन लागू है तथा ट्रेनों में भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए नियमित रूप से खाद्य नमूने लिए जाते हैं।
खानपान कर्मचारियों की दक्षता और सेवा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईआरसीटीसी द्वारा नियमित प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है, जिसमें संचार, विनम्र व्यवहार, सेवा मानक, व्यक्तिगत साज-सज्जा और स्वच्छता जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा पैंट्री कारों और बेस किचन में भोजन की स्वच्छता एवं गुणवत्ता की जांच के लिए तृतीय पक्ष ऑडिट तथा ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण भी किए जाते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों सहित रेलवे और आईआरसीटीसी के अधिकारी नियमित एवं औचक निरीक्षण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, कर्मचारियों की तैनाती, उपकरणों के रखरखाव, स्वच्छता और निर्धारित मानकों के अनुपालन की निगरानी करते हैं।

99.6% रेल नेटवर्क विद्युतीकृत, भारत ने रचा इतिहास

सूत्र/रे.स.ब्यू -भारतीय रेलवे ने रेल विद्युतीकरण के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देश के 99.6 प्रतिशत ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है। इस उपलब्धि के साथ भारत स्विट्जरलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे अधिक विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। रेल मंत्रालय के अनुसार, व्यापक विद्युतीकरण अभियान से रेलवे की डीजल पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आई है। डीजल की खपत घटकर लगभग 108 करोड़ लीटर रह गई है, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई है।
रेल मंत्रालय ने बताया कि रेल परिवहन, सड़क परिवहन की तुलना में लगभग 89 प्रतिशत कम कार्बन उत्सर्जन करता है। इसके अलावा रेलवे ने 1,260 मेगावाट से अधिक सौर और पवन ऊर्जा क्षमता भी स्थापित की है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिला है।
मंत्रालय का कहना है कि विद्युतीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से भारतीय रेलवे कम-कार्बन परिवहन प्रणाली विकसित करने और पर्यावरण संरक्षण के राष्ट्रीय लक्ष्य को मजबूत करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है।

कंटेनर ट्रेन कारोबार को मिली नई रफ्तार, सिंगल ऑल इंडिया लाइसेंस से सभी मार्गों पर संचालन आसान

भारतीय रेल ने लाइसेंसिंग व्यवस्था को बनाया सरल- सुधारों से परिवहन लागत और प्रदूषण में आएगी कमी, सड़कों पर भीड़भाड़ में राहत तथा उद्योग, विशेषकर एमएसएमई, को होगा लाभ

सूत्र/रे.स.ब्यू - भारतीय रेल ने भारतीय रेल नेटवर्क पर कंटेनर ट्रेनों के परिचालन के लिए ऑपरेटरों को अनुमति देने संबंधी मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट (एमसीए) में संशोधनों को मंजूरी दी है। स्वीकृत संशोधनों के तहत अब कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों (सीटीओ) को अलग-अलग मार्ग श्रेणियों के लिए पृथक अनुमति और शुल्क की मौजूदा व्यवस्था के स्थान पर 25 करोड़ रुपये के एकसमान पंजीकरण शुल्क के साथ सिंगल ऑल इंडिया लाइसेंस के आधार पर भारतीय रेल नेटवर्क के सभी मार्गों पर कंटेनर ट्रेनों का परिचालन करने की अनुमति होगी। इन संशोधनों को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।

सभी मार्गों के लिए एकल लाइसेंस

स्वीकृत संशोधनों के तहत लाइसेंस की वर्तमान मार्ग-वार श्रेणीकरण व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। रेल मंत्रालय की स्वीकृति के अधीन, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को सिंगल ऑल इंडिया लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, जिससे वे भारतीय रेल नेटवर्क के सभी मार्गों पर कंटेनर ट्रेनों का परिचालन कर सकेंगे।

एकसमान पंजीकरण शुल्क

विभिन्न मार्ग श्रेणियों के लिए अलग-अलग पंजीकरण शुल्क लेने की मौजूदा व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब प्रत्येक आवेदक को भारतीय रेल नेटवर्क के सभी मार्गों पर परिचालन के लिए 25 करोड़ रुपये का अप्रतिदेय एकसमान पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा।

लाइसेंस विस्तार पर कोई शुल्क नहीं

स्वीकृत संशोधनों के अनुसार, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर को दी गई अनुमति की अवधि समाप्त होने के बाद उसे आगे 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। यह विस्तार सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऑपरेटर के आवेदन तथा उसके संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किया जाएगा। इस विस्तार अथवा भविष्य में उसी ऑपरेटर को दिए जाने वाले किसी भी अन्य विस्तार के लिए कोई विस्तार शुल्क नहीं लिया जाएगा।

मौजूदा ऑपरेटरों को राहत

कैटेगरी-I लाइसेंसधारी ऑपरेटर अपनी वर्तमान श्रेणी के अंतर्गत अपनी कन्सेशन अवधि समाप्त होने तक परिचालन जारी रख सकेंगे। नई लाइसेंस व्यवस्था के तहत नवीनीकरण या विस्तार के समय उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
कैटेगरी-II, III और IV के ऑपरेटर भी अपनी वर्तमान श्रेणियों के अंतर्गत अपनी कन्सेशन अवधि पूरी होने तक परिचालन जारी रख सकेंगे। नई लाइसेंस व्यवस्था के तहत नवीनीकरण या विस्तार के लिए उन्हें 15 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। यह राशि नए 25 करोड़ रुपये के शुल्क और पहले से जमा किए गए 10 करोड़ रुपये के बीच का अंतर है। यह राशि अप्रतिदेय होगी।
ये ऑपरेटर अपनी 20 वर्ष की कन्सेशन अवधि पूरी होने से पहले भी नई लाइसेंस व्यवस्था में स्थानांतरित होने का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी उन्हें 15 करोड़ रुपये का ही भुगतान करना होगा।

उद्योग को लाभ

एकसमान पंजीकरण शुल्क तथा लाइसेंस विस्तार शुल्क समाप्त किए जाने से ऑपरेटरों के नियामकीय एवं अनुपालन संबंधी खर्चों में कमी आएगी तथा अनुमोदन प्रक्रिया सरल होगी।
सरल लाइसेंसिंग व्यवस्था से निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा तथा कंटेनर ट्रेन परिचालन का विस्तार होगा, जिससे देशभर में रेल आधारित माल परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा। कंटेनर परिवहन में रेल के अधिक उपयोग से उद्योग, विशेषकर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), की लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी, क्योंकि उन्हें अधिक दक्ष और लागत-प्रभावी माल परिवहन का विकल्प उपलब्ध होगा।
कंटेनर यातायात का सड़क से रेल की ओर अधिक स्थानांतरण होने से राष्ट्रीय राजमार्गों पर भीड़भाड़ कम होगी, ईंधन की खपत घटेगी तथा कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, जिससे अधिक टिकाऊ माल परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

एकसमान एवं सरल लाइसेंसिंग व्यवस्था की दिशा में

स्वींत संशोधनों का उद्देश्य भारतीय रेल नेटवर्क पर कंटेनर ट्रेन अ परेटरों के लिए एक सरल और एकरूप लाइसेंसिंग व्यवस्था स्थापित करना है। इन सुधारों से अनुमोदन प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी तथा म डल कन्सेशन एग्रीमेंट के अंतर्गत कंटेनर ट्रेन परिचालन के लिए एक समान नियामकीय ढांचा उपलब्ध होगा।

देशभर में 19 'रेल नीर' संयंत्रों से यात्रियों को सुरक्षित बोतलबंद पेयजल की आपूर्ति, हर संयंत्र की क्षमता 1 लाख बोतल प्रतिदिन

सूत्र/रे.स.ब्यू - भारतीय रेल देशभर में 19 'रेल नीर' संयंत्रों के माध्यम से महत्वपूर्ण ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को बोतलबंद पेयजल की आपूर्ति कर रही है। यात्रियों की मांग और आवश्यकता के अनुसार चिन्हित स्थानों पर रेल नीर संयंत्र स्थापित करने का कार्य भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) को सौंपा गया है। प्रत्येक रेल नीर संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 1 लाख बोतल है। पीपीपी मॉडल के तहत इतनी क्षमता वाले एक संयंत्र की अनुमानित लागत लगभग 10 करोड़ रुपये है, जिसमें प्री-इंजीनियर्ड बिल्डिंग शेड तथा प्लांट और मशीनरी की स्थापना शामिल है, जबकि भूमि की लागत इसमें शामिल नहीं है।
वर्तमान में नांगलोई (दिल्ली), दानापुर (बिहार), अंबरनाथ, नागपुर और भुसावल (महाराष्ट्र), पलुर (तमिलनाडु), मनेरी और मंडीदीप (मध्य प्रदेश), अमेठी और हापुड़ (उत्तर प्रदेश), ऊना (हिमाचल प्रदेश), जागीरोड (असम), संकराइल (पश्चिम बंगाल), कोटा (राजस्थान), साणंद (गुजरात), भुवनेश्वर (ओडिशा), बिलासपुर (छत्तीसगढ़), सिम्हाद्री और विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में 19 रेल नीर संयंत्र संचालित हैं। इन संयंत्रों के माध्यम से यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान बोतलबंद पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह जानकारी केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में दी।

भारतीय रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और सावंतवाड़ी रोड के बीच नई दैनिक एक्सप्रेस सेवा को मंजूरी दी

सूत्र/रे.स.ब्यू - महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में यात्री संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई) और सावंतवाड़ी रोड के बीच एक नई दैनिक एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है। यह नई सेवा 510 किलोमीटर के मार्ग पर सीधी, सुविधाजनक और विश्वसनीय रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे पर्यटन, शिक्षा, रोजगार, व्यापार और सामाजिक उद्देश्यों के लिए यात्र करने वाले हजारों यात्रियों को लाभ होगा।
प्रस्तावित ट्रेन प्रतिदिन ट्रेन संख्या 15087 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस-सावंतवाड़ी रोड एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 15088 सावंतवाड़ी रोड-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एक्सप्रेस के रूप में संचालित होगी।
नई दैनिक एक्सप्रेस सेवा दादर, थाने, पनवेल, पेन, रोहा, मनगांव, वीर, खेड़, चिपलुन, सवार्दा, अरावली रोड, संगामेश्वर रोड, रत्नागिरि, अदावली, वैलिवाडे, राजपुर रोड, वैभववाड़ी रोड, नंदगांव रोड, कांकवाली, सिंधुदुर्ग, कुदाल और सावंतवाड़ी रोड पर व्यावसायिक ठहराव प्रदान करेगी। इससे मुंबई महानगर क्षेत्र और कोंकण के महत्वपूर्ण कस्बों एवं जिलों के बीच सीधा संपर्क और बेहतर होगा तथा कोंकण तट तक पहुंच आसान होगी।
इस नई सेवा से पर्यटन, शिक्षा, रोजगार, व्यापार और सामाजिक उद्देश्यों के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों को लाभ मिलेगा। मुंबई और दक्षिणी कोंकण के बीच अतिरिक्त सीधी रेल सुविधा मिलने से क्षेत्र के समुद्र तटों, किलों, मंदिरों और पर्यावरण-पर्यटन स्थलों तक यात्रियों की पहुंच सुगम होगी। दैनिक यात्रियों, छात्रों, व्यापारियों, छोटे व्यवसायों और स्थानीय निवासियों को भी इससे सुविधा मिलेगी।

IRCTC Budget Hotel at Ekta Nagar Set for Ekta Diwas Commissioning

Shri Raju Bhadke, Divisional Railway Manager, Vadodara Division, inspected the under-construction IRCTC Budget Hotel at Ekta Nagar. Shri Gaurav Jha, Group General Manager (GGM), IRCTC, briefed him on the construction progress and passenger-centric amenities being developed at the facility. The hotel, being closely monitored by the Ministry of Railways, is planned to be commissioned on the occasion of Ekta Diwas. Once operational, it will offer comfortable, affordable and convenient accommodation to tourists and pilgrims visiting the Statue of Unity, helping reduce travel hassles and enhance the overall visitor experience at Ekta Nagar.

Somnath Railway Station Redevelopment Gains Momentum, Set to Enhance Pilgrim Travel Experience

Source/RSB- General Manager, Western Railway, conducted a review inspection of the under-construction Somnath Railway Station, taking stock of the progress of ongoing development works, infrastructure and passenger amenities. The redevelopment is progressing towards creating a modern, convenient and passenger-friendly railway station. With Somnath being an important pilgrimage destination, the upgraded station is expected to provide greater convenience and a more comfortable travel experience for pilgrims and visitors arriving to pay homage at the revered Somnath Temple.

DFCCIL Sets New Freight Performance Record with 19,371 Million GTKMs in July

Source / RSB - Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) achieved a new milestone in freight performance in July 2026, recording its highest-ever monthly Gross Tonne Kilometres (GTKMs) of 19,371 million. This represents a remarkable 21.73% growth over July 2025.

The record performance reflects the growing capacity, operational efficiency and strength of the Dedicated Freight Corridor network. The milestone further underscores DFCCIL's expanding role in enabling faster, heavier and more efficient freight movement across India, while strengthening the country's logistics ecosystem and supporting economic growth.

NFR Introduces GoLukBuk Digital Travel Assistance Kiosks at Guwahati Railway Station

In a significant step towards enhancing passenger convenience through digital innovation, Northeast Frontier Railway (NFR) inaugurated Digital Travel Assistance Kiosk Network at Guwahati Railway Station. The initiative, branded as GoLukBuk, marks the first-of-its-kind project in NFR and has been introduced under the New Innovative Non-Fare Revenue Ideas Scheme (NINFRIS).

The Digital Travel Assistance Kiosk Network was inaugurated by Shri Chetan Kumar Shrivastava, General Manager, Northeast Frontier Railway, in the gracious presence of Shri Niraj Sahay, Principal Chief Commercial Manager, Northeast Frontier Railway and other Senior officials.

As part of this initiative, strategically located digital kiosks have been installed at Guwahati Railway Station, with additional kiosks also planned at Kamakhya Railway Station, ensuring easy accessibility for passengers seeking travel assistance and digital booking services.

GoLukBuk is an integrated digital platform that enables passengers to conveniently compare and book a wide range of travel-related services through interactive kiosks. These include hotel accommodation, cab and car rental services, food and beverage delivery, sleeping pod bookings, meeting pod reservations and other travel assistance services from a single digital interface. The platform is designed to offer passengers a seamless, quick and user-friendly booking experience while reducing the need to access multiple applications or service providers.

The kiosks also feature high-resolution digital display screens and LED hologram fan technology, creating a modern Digital Out-of-Home (DOOH) advertising platform that offers businesses an opportunity to connect with thousands of railway passengers every day. Additional services, including Quick Commerce, are planned to be integrated in the near future to further expand the range of passenger amenities.

The project has been implemented under the NINFRIS scheme with an initial licence period of one year, extendable based on satisfactory performance. It also contributes to generating sustainable non-fare revenue while improving the overall passenger experience through technology-driven services.

The launch of GoLukBuk reflects Northeast Frontier Railway's commitment to enhancing passenger services through digital innovation. By offering a seamless and integrated travel assistance platform, the initiative aims to improve passenger convenience and set a benchmark for the adoption of similar technology-driven services at railway stations across the country.

Shri U. Subba Rao assumes charge as General Manager, Southern Railway

Source/RSB - Shri U. Subba Rao assumed charge as the General Manager of Southern Railway on 1st August 2026. Prior to this assignment, Shri Subba Rao served as the General Manager of the Integral Coach Factory (ICF), Chennai. An officer belonging to the 1987 batch of the Indian Railway Service of Mechanical Engineering (IRSME), Shri Subba Rao has held key leadership positions across various Zonal Railways and Production Units. Prior to his tenure as General Manager of the Integral Coach Factory (ICF), Chennai, he served as Additional General Manager and Principal Chief Mechanical Engineer of South Western Railway at Hubballi, Divisional Railway Manager (DRM) of Salem Division in Southern Railway, Chief Mechanical Engineer (Planning) of South Central Railway at Secunderabad, Chief Workshop Manager at the Coaching Workshop in Mysuru (SWR), and Chief Workshop Engineer at the Rail Wheel Factory, Bengaluru.

Known for his innovative approach at work and operational excellence, Shri Subba Rao, as Chief Workshop Engineer, played a pivotal role in achieving a record production of 2 lakh wheels in a single year (FY 2011-12) at Rail Wheel Factory, Bengaluru. Further, under his dynamic leadership as General Manager of ICF, the premier workshop received several prestigious national accolades such as the Best Production Unit Shield of Indian Railways, the Change Maker Award, the CII National Award, the Star Performer Award, and the National Energy Conservation Award for Innovation. Shri Subba Rao holds a Bachelor's degree in Mechanical Engineering and a Postgraduate Degree in Public Policy & Management from the Indian Institute of Management, Bengaluru. He has also undergone advanced executive training, including the Senior Managers' Programme in Paris and Johannesburg, and was actively involved in the validation of the EMU Cast Wheels Design at the Transportation Technology Center, Inc. (TTCI) in the USA.

Carrying forward a proud family legacy of exemplary public service, he is a second-generation Railway officer, succeeding his father, Shri U.Narasimha Rao, who retired as Chief Planning and Design Engineer from South Central Railway.

Rahul Himalian Gets Additional Charge of IRCTC CMD

Source/RSB - Rahul Himalian has been given the additional charge of Chairman and Managing Director (CMD) of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) following the resignation of Sanjay Kumar Jain from the post. Himalian is currently serving as Director (Tourism & Marketing) on the IRCTC Board and has been a Whole-Time Functional Director since February 16, 2024.

A 1999-batch officer of the Indian Railway Traffic Service (IRTS), he has more than 26 years of experience in the Indian Railways and IRCTC. In his present role, he oversees the corporation's Tourism, Information Technology, Human Resource Development, Infrastructure, Administration & Rajbhasha departments. Himalian graduated in Electrical Engineering with a Gold Medal from the National Institute of Technology (NIT), Hamirpur, and later completed his postgraduate studies in Engineering from the Indian Institute of Technology (IIT) Delhi.

EAST COAST RAILWAY MAINTAINS STRONG FREIGHT PERFORMANCE IN 2026–27

East Coast Railway has maintained a strong performance in freight transportation during the first four months of the financial year 2026–27. During the period from April to July 2026, ECoR recorded originating freight loading of 81.40 million tonnes (MT)

The achievement reflects the sustained focus of East Coast Railway on efficient freight operations, optimal utilisation of railway infrastructure and timely movement of freight traffic across its jurisdiction. The performance assumes significance in the backdrop of the recent reorganisation of the railway network and the formation of the new Rayagada Railway Division.

Among the divisions, Khurda Road Division handled 59.02 MT, while Rayagada Division recorded 13.71 MT and Sambalpur Division handled 8.67 MT during April–July 2026.

Rayagada Division Makes Strong Contribution

The newly formed Rayagada Railway Division has made a significant contribution to the freight performance of East Coast Railway. During April–July 2026, the division handled 13.71 MT of originating freight, reflecting its growing role in freight transportation within the reorganised railway network.

In July 2026 alone, Rayagada Division handled 3.14 MT of freight. Iron ore continued to be one of the major commodities handled by the division, with 2.28 MT loaded during the month. Bauxite loading stood at 0.19 MT.

Strong Freight Performance Across ECoR

The performance highlights the coordinated efforts of the Operating, Commercial, Engineering, Mechanical, Electrical and other departments of East Coast Railway in ensuring smooth and efficient freight operations.

The General Manager, East Coast Railway, appreciated the dedicated efforts of officers and staff across the Zone and called upon all concerned to sustain the momentum in freight transportation, further improve operational efficiency and strengthen customer-oriented freight services.

SOUTH EASTERN RAILWAY REGISTERS RECORD SERAP DISPOSAL PERFORMANCE - LEADS ALL ZONAL RAILWAYS

Source/RSB: South Eastern Railway has continued its outstanding performance in scrap disposal during the current financial year by achieving a record scrap sale of ₹201.20 Crore during the first four months (April-July 2026). This is the highest-ever scrap sale achieved by South Eastern Railway during the April-July period of any financial year. The revenue earned from scrap disposal is 31.85% higher than that achieved during the corresponding period of the previous financial year and 57.80% above the proportionate target for the period. With this achievement, South Eastern Railway is presently leading among all Zonal Railways in scrap disposal revenue and has become the first and only Zonal Railway to cross the 2200 crore mark during the first four months of the current financial year.

Scrap disposal is a priority area for Indian Railways as it not only generates substantial revenue but also supports the Government's Swachhta Abhiyan by ensuring cleaner railway premises, better utilization of railway assets and improved operational efficiency. This remarkable achievement has been possible under the guidance of General Manager, South Eastern Railway, Shri A. K. Jain, who has consistently emphasized the vision of achieving "Zero Scrap" across South Eastern Railway by October 2026.

In line with this vision, the Stores Department has undertaken a comprehensive zone-wide mapping and mopping exercise to identify segregate and dispose of accumulated scrap lying in depots, workshops, sheds and other railway establishments. As a result of these sustained efforts, South Eastern Railway has already achieved "Zero Scrap" status at 15 scrap-generating units up to July 2026.

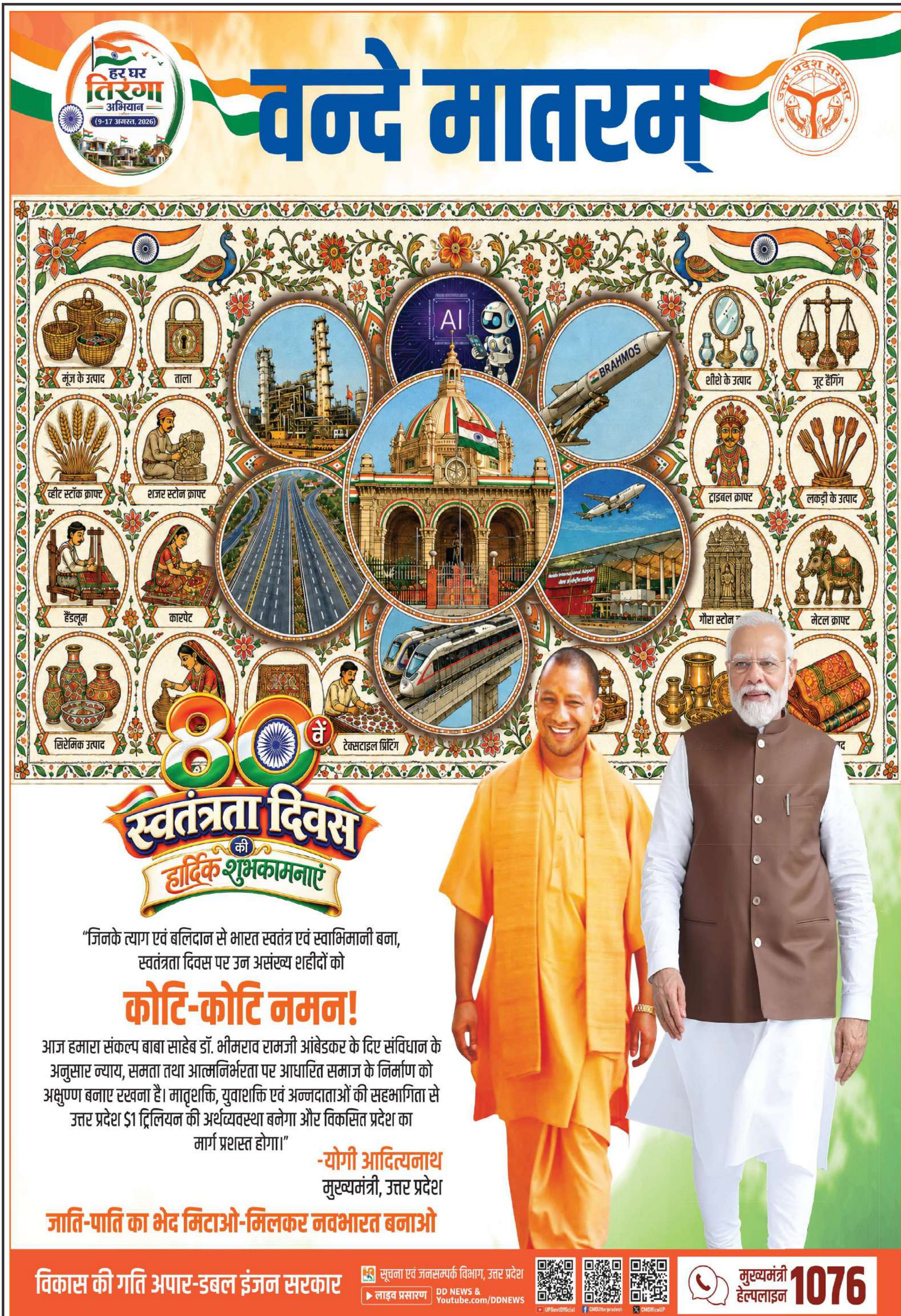
हर घर तिरंगा अभियान
(9-17 अगस्त, 2026)
वन्दे मातरम्
उत्तर प्रदेश सरकार
मूंज के उत्पाद
ताला
AI
BRAHMOS
शीशे के उत्पाद
जूट हैंगिंग
व्हीट स्टॉक क्राफ्ट
शजर स्टोन क्राफ्ट
ट्राइबल क्राफ्ट
लकड़ी के उत्पाद
हैंडलूम
कारपेट
गौरा स्टोन
मेटल क्राफ्ट
सिरेमिक उत्पाद
टेक्सटाइल प्रिंटिंग
80 वें
स्वतंत्रता दिवस
की
हार्दिक शुभकामनाएं
"जिनके त्याग एवं बलिदान से भारत स्वतंत्र एवं स्वाभिमानी बना,
स्वतंत्रता दिवस पर उन असंख्य शहीदों को
कोटि-कोटि नमन!
आज हमारा संकल्प बाबा साहेब डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर के दिए संविधान के अनुसार न्याय, समता तथा आत्मनिर्भरता पर आधारित समाज के निर्माण को अक्षुण्ण बनाए रखना है। मातृशक्ति, युवाशक्ति एवं अन्नदाताओं की सहभागिता से उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेगा और विकसित प्रदेश का मार्ग प्रशस्त होगा।"
-योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश
जाति-पाति का भेद मिटाओ-मिलकर नवभारत बनाओ
विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश
लाइव प्रसारण
DD NEWS &
Youtube.com/DDNEWS
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076